A Daily News Magazine
इंदौर
शुक्रवार, 06 फरवरी, 2026

इंदौर एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 11 अंक 126, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

भारत-यूएस ट्रेड डील से जुड़े तीन अनुत्तरित सवाल

राघवेंद्र राव

सोमवार दो फरवरी को भारत और अमेरिका ने एक नए व्यापार समझौते या ट्रेड डील की घोषणा की। पिछले कुछ वक्त से दोनों देशों के बीच रिश्तों में चल रही तल्ख़ी के मद्देनज़र इस समझौते ने रिश्तों में सुधार की उम्मीदें जगाई हैं। लेकिन समझौते की शर्तों और समयसीमा के बारे में न के बराबर जानकारी सार्वजानिक की गई है। हालांकि, भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार शाम को कहा कि अमेरिका के साथ भारत की ट्रेड डील पर अंतिम दौर की बातचीत में ब्योरे तय किए जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इस डील के बारे में जो कुछ लिखा उसमें से बहुत सी बातों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारत सरकार की तरफ़ से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं आई है।

और इसी वजह से इस डील से कई ऐसे सवाल खड़े हो गए हैं जिनके जवाब अभी तक मालूम नहीं हैं।

1. **क्या वाक़ई भारत अब रूस से तेल नहीं ख़रीदेगा?:** राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि भारत रूस से तेल ख़रीदना बंद करने और अमेरिकी तेल की ख़रीद बढ़ाने पर राज़ी हो गया है। उन्होंने यह तक कहा कि भारत वेनेज़ुएला से भी तेल ख़रीद सकता है। लेकिन भारतीय पक्ष ने इन बयानों पर कोई स्पष्ट पुष्टि नहीं की है। तो क्या यह दावा सिर्फ़ राजनीतिक बयानबाज़ी भी हो सकता है?

जाने-माने अर्थशास्त्री प्रोफ़ेसर बिस्वजीत धर कहते हैं कहते हैं, 'देखिए हमारी सरकार का आधिकारिक रुख़ था कि हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा का अपने हिसाब से निर्धारण करेंगे। और उसका बड़ा साफ़ संकेत था कि हमें अगर रूस से सस्ते में तेल मिल रहा है तो हम वहीं से खरीदेंगे। अभी राष्ट्रपति ट्रंप ने जो कहा है कि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, यह भारत सरकार के पहले अपनाये गए रुख़ के उलट है। मतलब यह है कि अमेरिका अब हमें डिक्टेट कर रहा है कि कैसे हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा को हासिल करें। तो मेरे हिसाब से यह तो बहुत बड़ा कम्प्रोमाइज़ है।' मोहन कुमार फ्रांस में भारत के राजदूत रह चुके हैं और अंतरराष्ट्रीय व्यापार और बहुपक्षीय वार्ता के क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। वह कहते हैं, 'समझौते की पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। इसलिए इस पर टिप्पणी करना फ़िलहाल मुश्किल है।मेरी जानकारी में भारत ने पहले ही रूसी तेल की ख़रीद काफ़ी कम कर दी है।'

2. **क्या भारत 500 अरब डॉलर के अमेरिकी उत्पाद ख़रीदेगा?:** राष्ट्रपति ट्रंप के दावे का एक और अहम पहलू यह है कि भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर मूल्य के ऊर्जा, तकनीक और कृषि उत्पाद ख़रीदेगा। असलियत यह है कि भारत का कुल सालाना अमेरिकी आयात अभी 50 अरब डॉलर से भी कम है। तो क्या यह दावा हवाई है?

प्रोफ़ेसर बिस्वजीत धर कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को बड़े साफ़ तौर पर कहा था कि हमारे किसानों के हितों से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। यानी भारत के जो छोटे किसान हैं उनकी रोज़ी-रोटी सुरक्षित है। खाद्य सुरक्षा के मामले में आज हम आत्मनिर्भर हैं। अब उस आत्मनिर्भरता के ऊपर आंच आती दिख रही है। प्रोफ़ेसर धर के मुताबिक़, अमेरिका की कृषि सचिव ने कहा है कि हम भारत को निर्यात करेंगे और हमारे (अमेरिकी) किसानों को उनको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। तो आधिकारिक तौर पर उनकी तरफ से यह आ रहा है। कृषि और ऊर्जा- जो दो मौलिक चीज़ें हैं हमारे देश के लिए- वहां पर अगर हम अमेरिका के ऊपर इम्पोर्ट-डिपेंडेंट (आयात पर निर्भर) हो जाते हैं, जो हमने पहले बिल्कुल मना कर दिया था और कहा था कि इन पर हम समझौता नहीं करेंगे और ये हमारे संप्रभु फ़ैसले रहेंगे, तो मुझे इस बात से दिक़्क़त हो रही है कि यह जो डील है यह विश्वासघात न हो गया हो।'

पीयूष गोयल ने मंगलवार शाम में कहा था, ''इंडिया और यूएस डील के तहत एग्रीकल्चर और डेयरी जैसे संवेदनशील सेक्टर को लेकर, उनको संरक्षण दिया गया है। गोयल ने कहा कि जैसे ही अंतिम सहमति बन जाती है, सारा विवरण सार्वजनिक किया जाएगा। तो भारत के अमेरिका से 500 अरब डॉलर का सामान ख़रीदने की क्या संभावना है? मोहन कुमार कहते हैं कि उन्होंने 'गोइंग फॉरवर्ड' शब्द का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब है कि यह आगे आने वाले समय में एक लंबी अवधि में होगा। यह देखने की ज़रूरत होगी कि दोनों पक्षों ने किस समय अवधि पर सहमति बनाई है। अतीत में कई ऐसे मौक़े आए हैं जब ट्रंप अपनी कही गई बातों या दावों से पीछे हटते दिखे हैं। क्या भारत के साथ हुई डील पर उनके किए गए दावों का भी यही हश्र हो सकता है? प्रोफ़ेसर धर कहते हैं कि ऊर्जा और कृषि दोनों ही राष्ट्रपति ट्रंप के लिए मौलिक मुद्दे हैं। भारत 500 अरब डॉलर का आयात करेगा तो ऐसे ही नहीं कह सकते हैं क्योंकि इस बयान के ग़लत साबित होने पर राजनीतिक परिणाम काफ़ी गंभीर हो सकते हैं।'

3. **क्या भारत अमेरिका पर सभी टैरिफ और ग़ैर-टैरिफ बाधाएं हटाएगा?:** सोशल मीडिया ट्रूथ सोशल पर अपने पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर समस्त टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाएं 'ज़ीरो' या शून्य कर देगा। लेकिन भारत ने अब तक किसी भी आधिकारिक बयान में इसका ज़िक्र नहीं किया है। भारत परंपरागत रूप से कृषि, जीएम खाद्य उत्पादों और संवेदनशील श्रेणियों में विदेशी आयात के प्रति सतर्क रहता है और इन क्षेत्रों में बाज़ार खोलने की संभावना बेहद कम मानी जाती है। प्रोफ़ेसर धर कहते हैं कि अतीत में भारत का रुख़ यह रहा है कि विकसित देशों को ज़्यादा टैरिफ़ और विकासशील देशों को कम टैरिफ़ देना चाहिए। अब यह बात पूरी तरह से उलट गई है। जो बयान आए हैं उनके मुताबिक़ अमेरिका ज़ीरो परसेंट टैरिफ देगा। ट्रंप के आने से पहले भारत पर जो टैरिफ़ औसतन सिर्फ़ ढाई फ़ीसदी लगता था वह अब 18 फ़ीसदी हो गया है और भारत जो अमेरिका पर लगाता था अगर वह शून्य हो जाता है तो ये तो बिल्कुल ही एक तरह से उलटफेर हो गया है। भारत का बहुत ज़्यादा घाटा है इसमें। अब आप अगर मार्केट को पूरी तरह से खोल देते हैं तो एमएसएमई का बहुत बड़ा नुक़सान है।'

दोनों देशों के बीच हुई डील के फ़ाइन प्रिंट के बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके बावजूद मोहन कुमार कहते हैं, 'यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक समझौता है।

(बीबीसी हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोले पीएम मोदी

दुनिया के 9 बड़े देशों के साथ हुई ट्रेड डील

विपक्ष का भारी नारेबाजी के बाद वॉकआउट

नई दिल्ली (एजेंसी)। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दिया। पीएम मोदी ने भाषण की शुरुआत में पीएम मोदी ने विकसित भारत की यात्रा का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण का जिक्र करते हुए कहा कि राष्ट्रपति के भाषण में देश के विकास का स्वर संसद में गूंजा है। उन्होंने कहा कि देश का समर्थ कैसे आगे बढ़ रहे हैं इसकी चर्चा राष्ट्रपति के भाषण में हुई है। उन्होंने कहा कि 21वी सदी का पहला क्वार्टर पूरा हो चुकी है। पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत की निर्माण की दिशा में दूसरा क्वार्टर भी उतना ही सामर्थवान होने वाला है।

● **चुनौतियों का समाधान देने वाला देश-** पीएम मोदी ने कहा कि शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है। भारत आज विश्व में चुनौतियों का समाधान देने वाले देश और आशा की किरण बना हुआ है। उन्होंने कहा कि हम समाधान दे रहे हैं। पीएम ने कहा कि भारत का ग्रोथ बहुत हाई है। यह हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूती को प्रदर्शित करता है। पीएम ने कहा कि हम जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं, आज हम दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज सांइस, स्पेस, स्पोर्ट्स हर क्षेत्र में भारत आज आत्मविश्वास से भरा हुआ है। दुनिया आज नए ग्लोबल ऑर्डर की तरफ बढ़ रहा है। पीएम ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक वर्ल्ड ऑर्डर बना था। अब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। इसमें झुकाव भारत की तरफ है। उन्होंने कहा कि विश्व मित्र के रूप में, विश्व बंधु के रूप में आज भारत अनेक देशों का विश्वस्त पार्टनर बना है। हम कंधे से कंधा मिलाकर विश्व कल्याण की दिशा में अपनी उचित भूमिका निभा रहे हैं। पीएम ने कहा कि आज पूरा विश्व ग्लोबल साउथ की चर्चा कर रहा है लेकिन भारत आज ग्लोबल साउथ की आवाज बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज भारत फ्यूचर रेडी ट्रेड डील कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले कुछ समय में दुनिया के 9 बड़े देशों के साथ हमारी ट्रेड डील हुई है।

लोकसभा में बिना भाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पारित

लोकसभा ने बृहस्पतिवार को विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया। धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन में हुई चर्चा का प्रधानमंत्री द्वारा सदन में जवाब देने की परंपरा है, लेकिन गतिरोध की स्थिति के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जवाब लोकसभा में नहीं हुआ और प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। कांग्रेस ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित होने को लेकर सवाल उठाए।

शरद की सुबह

एक ख़त जो किसी ने लिखा भी नहीं
उम्र भर आँसुओं ने उसे ही पढ़ा।
गंध डूबा हुआ एक मीठा सपन
कर गया प्रार्थना के समय आचमन।
जब कभी गुनगुनाने लगे बाँसवन
और भी बढ़ गया प्यास का आयतन।
पीठ पर काँच के घर उठाए हुए
कौन किसके लिए पर्वतों पर चढ़ा।
जब कभी नाम देना पड़ा प्यास को
मौन ठहरे हुए नील आकाश को।
कौन संकेत देता रहा क्या पता
होंठ गाते रहे सिर्फ़ आभास को।
मोम के मंच पर अग्नि की भूमिका
एक नाटक यही तो समय ने गढ़ा।
एक ख़त जो किसी ने लिखा भी नहीं
उम्र भर आँसुओं ने उसे ही पढ़ा।

– शतदल

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने हरिद्वार में संत सम्मेलन को किया संबोधित

भारत को हिंदुत्व पर गर्व है और हिंदुत्व ही राष्ट्रत्व है : मुख्यमंत्री

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सनातन संस्कृति को नए आयाम तक पहुंचाने में आदि शंकराचार्य का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। मध्यप्रदेश की धरा से आदि शंकराचार्य जी का विशेष संबंध रहा है। वैचारिक स्तर पर भारत को हिंदुत्व पर गर्व है, हिंदुत्व ही राष्ट्रत्व है। सनातन की धारा शाश्वत रूप से बहती रहे, इस उद्देश्य से संतवृंद और सरकार समन्वित रूप से प्रयासरत है। हरिद्वार में समन्वय सेवा ट्रस्ट द्वारा स्थापित भारत माता मंदिर समाज और राष्ट्र में ऊर्जा का संचार कर रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुरूवार को हरिद्वार में समन्वय सेवा ट्रस्ट द्वारा आयोजित गुरुदेव समाधि मंदिर मूर्ति स्थापना समारोह के अंतर्गत संत सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर जूनापीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि महाराज ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव को सिंहस्थ-2028 के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दीं।

संत महात्माओं को दिया सिंहस्थ-2028 का निमंत्रण- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आदि शंकराचार्य जी की परंपरा के संवाहक, वैदिक सनातन संस्कृति के उन्नायक, देश के प्रथम भारत माता मंदिर के संस्थापक पद्मभूषण स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार भव्य और दिव्य सिंहस्थ के आयोजन के लिए सभी व्यवस्थाओं और विकास कार्यों पर ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी संत महात्माओं को सिंहस्थ-2028 के लिए उज्जैन पधारने के लिए निमंत्रण दिया।

जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने कहा कि संतवृंद के आशीर्वाद से देश में पिछले वर्षों में हुआ बदलाव अद्भुत है। भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया है और तेजी से एक विकसित राष्ट्र के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, वॉटरवेज, हाई स्पीड रेल, हाईवेज से देश की युवा शक्ति और अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिली है। देश की बहनें, किसान, युवा सभी समावेशी विकास के मार्ग पर अग्रसर हैं। सांस्कृतिक समृद्धि, विरासत संरक्षण और धार्मिक पर्यटन में भी पूरे राष्ट्र में एक नई चेतना जागृत हुई है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने योगगुरू स्वामी रामदेव जी के साथ किया योगाभ्यास

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरूवार को पतंजलि योगपीठ, हरिद्वार में योगगुरु स्वामी रामदेव जी के साथ योगाभ्यास किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में योग आज भारत की प्राचीन परंपरा से निकलकर वैश्विक जन-आंदोलन बन चुका है। हम सभी योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और स्वस्थ, संतुलित व ऊर्जावान जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पतंजलि योगपीठ के वातावरण से प्रभावित होकर कहा कि योगपीठ का संस्कार, साधना और आत्मबल से परिपूर्ण वातावरण मन को अपार शांति प्रदान करता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने योगगुरु स्वामी रामदेव जी के साथ हरिद्वार में भारत माता मंदिर में दर्शन, पूजन और यज्ञ में शामिल होकर सभी के मंगल एवं कल्याण की कामना की।

जल्द ही बुलेट ट्रेनों के निर्माण में आत्मनिर्भर होगा भारत

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में कहा कि भारत जल्द ही बुलेट ट्रेनों के निर्माण में 100 फीसदी आत्मनिर्भर होगा। उन्होंने कहा कि नए बजट में घोषित सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर में स्वदेशी तकनीकों का उपयोग किया जाएगा और भारत के पास जल्द ही अपनी बुलेट ट्रेन होगी। यह बातें मंत्री ने एक इंटरव्यू में कहीं।

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय रेलवे ने हाई-स्पीड रेल प्रणालियों की जटिलताओं को पूरी तरह से समझ लिया है और उन्हें लागू करने के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि भूमि अधिग्रहण इस परियोजना के लिए मुख्य चुनौतियों में से एक होगा और सभी राज्यों को इसका समर्थन करना चाहिए क्योंकि यही लोगों का हक और इच्छा है।

पश्चिम बंगाल में कांग्रेस नहीं करेगी किसी से गठबंधन

● सभी 294 सीटों पर अकेले लड़ेगी चुनाव, सरगर्मी हुई तेज

कोलकाता (एजेंसी)। इसके साथ ही कांग्रेस बंगाल की सभी 294 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। यह फैसला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को पार्टी की अहम बैठक में लिया। इसमें पश्चिम बंगाल के कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद थे। दरअसल सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से बड़ी चुनौती मिल रही है। इसके बावजूद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी ने विपक्ष के इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद कांग्रेस या किसी सहयोगी के साथ गठबंधन पर कोई बातचीत शुरू नहीं की है। इसके चलते कांग्रेस ने यह कदम उठाया है।

पीएम के साथ बुधवार को कुछ भी हो सकता था

● मैंने लोकसभा न आने का आग्रह किया, स्पीच टाली ● स्पीकर बोले,विपक्षी महिला सांसदों ने कुर्सी घेरी थी

नई दिल्ली (एजेंसी)। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने गुरुवार को कहा- बुधवार को लोकसभा में पीएम मोदी के साथ अप्रत्याशित घटना हो सकती थी। इसलिए उनकी कल शाम 5 बजे होने वाली स्पीच टालनी पड़ी। आशंका के चलते मैंने ही उनसे न आने का आग्रह किया था। दरअसल, पीएम मोदी 5 फरवरी को लोकसभा में शाम 5 बजे धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देने वाले थे, लेकिन विपक्ष की महिला सांसदों के हंगामे के चलते स्पीकर संध्या राय ने कार्यवाही अगले दिन तक स्थगित कर दी। इससे पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन भी टल गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा- कल लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय में जो हुआ, वह सदन के इतिहास में कभी नहीं हुआ। जब सदन के नेता पीएम मोदी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था तो विपक्षी सांसद प्रधानमंत्री की सीट के पास पहुंचकर कोई अप्रत्याशित घटना कर सकते थे।

सांसदों का आचरण हमारी संसदीय परंपराओं के खिलाफ

लोकसभा अध्यक्ष ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, विपक्ष के सदस्यों ने अध्यक्ष के कार्यालय में जो व्यवहार किया। वह हमारी संसदीय परंपराओं के लिए अनुचित था। वह पल एक काले धब्बे की तरह था। हम सबको सदन सुचारु रूप से चलाने में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा, कि पीएम मोदी को राष्ट्रपति के अधिभाषण का जवाब देना था तो मेरे पास पुख्ता जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य प्रधानमंत्री के आसन तक पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। अगर यह घटना हो जाती तो यह अत्यंत अप्रिय है।

भोपाल का तापमान
अधिकतम 20°c न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

इंदौर ■ शुक्रवार, 06 फरवरी 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है; यह अग्नि का दोष नहीं है।
चाणक्य नीति

चाइनीज मांझे से हुई मौत हत्या मानी जाएगी

● सीएम योगी ने पुलिस अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

नई दिल्ली (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चाइनीज मांझे से होने वाले हादसों पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने इस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है और पुलिस अधिकारियों को पूरे राज्य में छापेमारी करके इसकी अवैध बिक्री को रोकने का निर्देश दिया है। उन्होंने चाइनीज मांझे के खिलाफ पूरे राज्य में अभियान चलाने का आदेश दिया है। साथ ही कहा कि चाइनीज मांझे से होने

वाली किसी भी मौत को हत्या माना जाएगा और पूरे ऑपरेशन की समीक्षा उच्चतम स्तर पर की जाएगी। लखनऊ के बुलाकी अड्डा स्थित हैदरगंज पुल के पास बुधवार की शाम बाइक से जा रहे 33 वर्षीय मोहम्मद शोएब की गर्दन में मांझा फंस गया था।

शोएब कुछ समझ पाते इसके पहले ही मांझे से उनकी गर्दन की नसें कट गई। किसी तरह उन्होंने बाइक रोकी और अचेत होकर सड़क पर गिर गए। राहगीरों की मदद से उन्हें ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। इस हादसे का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी ने सख्त रुख अपनाया है। बता दें, लखनऊ के दुबग्गा के मछली मंडी निवासी शोएब निजी कम्पनी में मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिव (एमआर) थे। बड़े भाई शारिक के मुताबिक, शोएब बुधवार दोपहर बाइक से हेलमेट लगाकर कंपनी के काम से चौक से हैदरगंज की तरफ जा रहे थे।

जल्द आएगा भारत-अमेरिका ट्रेड डील का जॉइंट स्टेटमेंट

● पीयूष गोयल बोले-मिड-मार्च तक पहला ट्रांच फाइनल होने की उम्मीद

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच बाइलेटरल ट्रेड डील पर जॉइंट स्टेटमेंट अगले 4-5 दिनों में फाइनल और साइन हो सकता है। उन्होंने बताया कि यह डील का पहला ट्रांच है और इसका लीगल टेक्स्ट मिड-मार्च तक तैयार हो जाएगा। गोयल ने संसद में और मीडिया से

बातचीत में यह जानकारी दी। पीयूष गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत तेजी से चल रही है। जॉइंट स्टेटमेंट साइन होने के बाद अमेरिका भारतीय गुड्स पर टैरिफ घटाकर 18 फीसदी कर देगा। गोयल ने बताया कि यह वर्चुअल तरीके से भी साइन हो सकता है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका कॉम्प्लिमेंट्री इकोनॉमी हैं, यह डील दोनों के लिए फायदेमंद होगी। गोयल ने स्पष्ट किया कि एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को इस डील में फुली प्रोटेक्ट किया गया है। फ्रेमवर्क अंडरस्टैंडिंग में दोनों देशों के क्रिटिकल और सेंसिटिव सेक्टर सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों की एनर्जी सिक्योरिटी सरकार की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। इस डील में कोई इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट नहीं है।

पीएम से सदन में न आने का आग्रह मैंने खुद किया

● बिरला बोले-कांग्रेस के कई सदस्य अप्रिय घटना कर सकते थे

महिला सांसदों के घेरे पर स्पीकर ओम बिरला का बड़ा बयान

नई दिल्ली (एजेंसी)। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को कहा कि कल सदन में कांग्रेस के कई नेता सदन के नेता के आसन के पास पहुंचकर किसी अप्रत्याशित घटना को अंजाम देना चाहते थे, इसलिए उनके अनुरोध पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सदन में नहीं आए। बिरला ने यह भी कहा कि बुधवार को विपक्ष के कुछ सदस्यों ने उनके चैंबर में आकर जिस तरह का व्यवहार किया, वैसा लोकसभा की शुरुआत से लेकर आज तक कभी नहीं हुआ और यह दृश्य एक 'काले धब्बे' की तरह था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को कहा, इस सदन में बुधवार को कुछ सदस्यों ने जिस प्रकार का व्यवहार किया, वो लोकसभा की शुरुआत से लेकर आज तक कभी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, कि आज तक इतिहास रहा है कि राजनीतिक मतभेदों को आज तक सदन के कार्यालय तक नहीं लाया गया है।

सांसदों का आचरण हमारी संसदीय परंपराओं के खिलाफ

लोकसभा अध्यक्ष ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, विपक्ष के सदस्यों ने अध्यक्ष के कार्यालय में जो व्यवहार किया। वह हमारी संसदीय परंपराओं के लिए अनुचित था। वह पल एक काले धब्बे की तरह था। हम सबको सदन सुचारु रूप से चलाने में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा, कि पीएम मोदी को राष्ट्रपति के अधिभाषण का जवाब देना था तो मेरे पास पुख्ता जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य प्रधानमंत्री के आसन तक पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। अगर यह घटना हो जाती तो यह अत्यंत अप्रिय है। यह देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार-तार कर देता। इस घटना को टालने के लिए मैंने पीएम मोदी से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए।

जनगणना शुरू होते ही नहीं पूछी जाएगी जाति

● जाति जनगणना के लिए अभी करना होगा इंतजार

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत की आगामी जनगणना को लेकर केंद्र सरकार ने संसद में बड़ी जानकारी दी है। सरकार ने साफ-साफ कहा है कि

जनगणना की प्रक्रिया शुरू होती ही जाति जनगणना नहीं शुरू होगी। इसके लिए लोगों को दूसरे चरण का इंतजार करना पड़ेगा। राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि जाति से संबंधित सवालों को दूसरे चरण की शुरुआत से पहले अधिसूचित किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि देश में होने वाली जनगणना का काम दो हिस्सों में बांटा गया है।

22 जवानों का हत्यारा खूंखार नक्सली एनकाउंटर में ढेर

● सुरक्षाबलों ने घेरकर किया ढेर, साथ में रखता था एके 47

बीजापुर (एजेंसी)। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में सुरक्षाबल के जवानों को बड़ी सफलता मिली है। जवानों और माओवादियों के बीच एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर में एक टॉप नक्सली मारा गया है। सूत्रों के अनुसार, मारे गए नक्सली की पहचान कमांडर उधम सिंह के रुप में हुई है। बस्तर में ऐक्टिव वह खूंखार नक्सली थी। उसके सिर पर 8 लाख रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, उधम सिंह साल 2021 में हुए टेकुलगुड़ेम नक्सली हमले में शामिल था। जहां नक्सली हमले में 22 जवान शहीद हुए थे। इसके साथ ही वह कई वारदातों में शामिल रहा। उधम सिंह टेकुलगुड़ेम नक्सली हमले को अंजाम देने वाले टॉप लीडरों में था। ऐसा कहा जाता है कि वह इस हमले की प्लानिंग में भी शामिल था। उधम सिंह प्लाटून नंबर 30 का कमांडर था। इसके साथ उसके पास जागूरगुंडा एरिया कमेटी की भी जिम्मेदारी थी। सुरक्षाबलों से मिली जानकारी के अनुसार, इसके सिर पर 8 लाख रुपये का ईनाम घोषित था।

हिंसा और धमकियों के सिस्टमैटिक पैटर्न को रोकिए...

सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर बोला चुनाव आयोग

नई दिल्ली (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से तुरंत दखल देने की मांग की है। आयोग ने कोर्ट से कहा है कि एसआईआर का काम कर रहे अधिकारियों के खिलाफ हिंसा और धमकियों के एक सिस्टमैटिक पैटर्न को रोका जा सके। आयोग ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के भाषणों से ऐसी स्थितियों को बढ़ावा मिला, जबकि पुलिस दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी कर रही है। ईसी ने अपने हलफनामे में कहा,यह साफ तौर पर दिखाता है कि पश्चिम बंगाल में आने वाली चुनौतियां एसआईआर प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हैं,बल्कि ये राज्य मशीनरी की कमियों और राजनीतिक दखल का सीधा नतीजा हैं।

● मेघालय में अवैध कोयला खदान में हुआ धमाका

16 की मौत, कई घायल

नईदिल्ली (एजेंसी)। मेघालय के पूर्वी जंयतिया हिल्स जिले में गुरुवार को एक बड़ा हादसा हो गया है, यहां एक अवैध कोयला खदान में बड़ा धमाका हो गया, जिसमें कम से कम 16 लोगों के मारे जाने और कई लोगों के घायल होने की खबर है। धमाके का कारण डायनामाइट का फटना बताया जा रहा है।

पुलिस ने घटनास्थल पर बचाव अभियान चलाने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) से सहायता मांगी है। इधर राज्य डीजीपी ने बताया कि अवैध कोयला खदान में हुए विस्फोट में 16 मजदूरों की मौत हो गई, कई अन्य के फंसे होने की आशंका है।

कहां हुआ ये धमाका?

मीडिया सूत्रों के मुताबिक, पुलिस ने बताया कि पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले के एक गांव में संदिग्ध अवैध कोयला खदान में धमाका हुआ है, इसमें एक व्यक्ति घायल हो गया है और खदान में कई मजदूर फंस गए हैं। पूर्वी जयंतिया हिल्स के पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि यह घटना थांगस्कू इलाके में हुई। खदान में काम कर रहे सात लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं और एक व्यक्ति जो 70 प्रतिशत तक झुलस गया है, उसे इलाज के लिए राज्य की राजधानी शिलांग भेजा गया है। बचाव दल और अधिकारी अभी यह पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं कि खदान के अंदर कितने और लोग फंसे हो सकते हैं।

बंगाल की महिलाओं को 1700 तो बेरोजगारों को 1500 हर महीने

● चुनाव से पहले बंगाल के बजट में ममता दीदी के बड़े ऐलान

कोलकाता (एजेंसी)। चुनाव आयोग से भिड़ंत और चुनावी सुगबुगाहट के बीच पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार ने गुरुवार को 2026-27 का बजट पेश कर दिया है। 4.06 लाख करोड़ रुपये के अंतरिम बजट में सीएम ममता बनर्जी ने खजाना खोल दिया है। युवाओं को बेरोजगारी भत्ते से लेकर महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद की राशि को बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है। वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने गुरुवार को प्रदेश का अंतरिम बजट पेश किया है। बजट में सबसे बड़े ऐलान महिलाओं और युवाओं के लिए किए गए हैं। महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद देने वाली लक्ष्मी भंडार योजना के भत्ते में 500 रुपये महीने की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा प्रदेश के बेरोजगारों के लिए युवा साथी योजना का ऐलान किया गया है। इसके तहत बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपये महीना मिलेंगे। लक्ष्मी भंडार योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1000 से 1200 रुपये महीने मिलते हैं। अब इनमें 500 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा हुई है।

सेवा में रहते हुए बार-बार परीक्षा देने का रास्ता बंद

● रैंक सुधारने का मौका सिर्फ एक बार, नए नियम 2026 से लागू

नई दिल्ली (एजेंसी)। संघ लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) ने सिविल सेवा परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन बुधवार को जारी किया है। आयोग ने इस बार 933 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया है। आवेदन की आखिरी तारीख 24 फरवरी है। परीक्षा केंद्र में फेस ऑथेंटिकेशन के बाद ही एंट्री दी जाएगी। इस बार प्रयास और पात्रता से जुड़े नियमों में भी बड़ा बदलाव किया गया है। इसके मुताबिक अब सिलेक्शन के बाद दोबारा परीक्षा देने की आजादी पहले जैसी नहीं रहेगी। नए प्रावधानों में सेवा में रहते हुए बार-बार परीक्षा देने का रास्ता बंद कर दिया गया है। वहीं, बाकी पुराने नियम जस के तस रखे गए हैं। चयनित अफसर को एक बार परफॉर्मेंस बेहतर करने का मौका मिलेगा। जैसे किसी का 2026 में ग्रेड में सिलेक्शन हुआ तो वह 2027 में परफॉर्मेंस बेहतर करने की परीक्षा देने का पात्र होगा।

● **ये बदलाव यूपीएससी 2026 में पहली बार दिखेंगे-**
सिविल सर्विस एग्जाम-2026 में अगर ग्रुप-ए या फिर आईपीएस मिलती है, तो उम्मीदवार को सिर्फ एक बार यानी सीएसई-2027 में रैंक सुधारने का मौका मिलेगा। मौका तभी मिलेगा जब उम्मीदवार को ट्रेनिंग जॉइन न करने की वन टाइम एक्जेम्शन (एक बार की छूट) मिले। छूट फाउंडेशन कोर्स तक सीमित होगी। यदि उम्मीदवार न ट्रेनिंग जॉइन करता है, और न छूट लेता है, तो सीएसई-2026 अपने आप रद्द होगी।

पुणे से मिलने आया युवक, लड़की ने डोसा खिलाया और कमरे में ले गई

ऑनलाइन प्यार के जाल में फंसा युवक

मैहर (नप्र)। सोशल मीडिया पर अनजान चेहरों से दोस्ती करना कितना घातक हो सकता है, इसका एक जीता-जागता उदाहरण एमपी के मैहर जिले में सामने आया है। यहां इंस्टाग्राम पर पनपी दोस्ती एक युवक के लिए डरावने सपने में बदल गई। हनीट्रैप के इस मामले में एक युवती ने पुणे में नौकरी करने वाले युवक को मिलने के बहाने मैहर बुलाया, डोसा खिलाया और फिर अपने कमरे पर ले जाकर साथियों के साथ मिलकर उसे निर्वस्त्र कर वीडियो बना लिया।

आरोपियों ने युवक को रेप केस में फंसाने की धमकी देकर 56 हजार रुपये वसूल लिए। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए युवती समेत 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है।

पुणे से मैहर खींच लाया 'वर्चुअल प्यार' - फरियादी शिवशंकर गुप्ता मूल रूप से मैहर के भदनपुर पहाड़ का निवासी है और पुणे में काम करता है। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि 10 दिन पहले इंस्टाग्राम पर उसकी दोस्ती मानसी उर्फ गोल्डी नाम की युवती से हुई। चैटिंग और कॉलिंग से भरोसा बढ़ा, तो युवती ने उसे मिलने के लिए मैहर बुला लिया। 3 फरवरी को युवक पुणे से मैहर पहुंचा। शाम 7:30 बजे घंटाघर चौक पर दोनों मिले। इसके बाद दोनों ने इंडियन काफी हाउस में जाकर डोसा खाया।

पानी के बहाने रूम में कराई एंट्री- नाश्ते के बाद युवती ने शिवशंकर से कहा कि उसे घुरपुरा स्थित उसके किराए के कमरे तक छोड़ दे। कमरे पर पहुंचने पर उसने पानी पीने के बहाने युवक को अंदर बुला लिया। हालांकि युवक ने पहले अंदर आने से इनकार लेकिन युवती के कहने पर अंदर चला गया। जैसे ही युवक अंदर बैठा, युवती ने फोन घुमाया। कुछ ही देर में वहां विक्की गुप्ता (लटागांव), मनोज उर्फ माचो, फूलचंद कुशवाहा और एक अन्य युवक आ धमके। आरोपियों ने आते ही युवक को गालियां दीं और पीटना शुरू कर दिया। विरोध करने पर हाथ-पैर और घुटनों पर चोटें पहुंचाईं। इसके बाद जबरन उसके कपड़े उतरवाकर उसे निर्वस्त्र कर दिया।

आरोपियों ने नग्न अवस्था में युवक का वीडियो बनाया। युवती ने धमकी दी कि चुपचाप पैसे दे दो, वरना रेप के झूठे केस में फंसाकर वीडियो वायरल कर देंगे।

13 दिन में दूसरी बार गौवंश का कटा सिर-पैर मिला

मंदसौर में हिंदू संगठनों ने किया चक्काजाम; आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग

मंदसौर (नप्र)। मंदसौर में 13 दिनों के भीतर दूसरी बार गौवंश के अवशेष मिलने से तनाव की स्थिति बन गई है। गुरुवार दोपहर करीब 3:30 बजे शहर के नयापुरा से सटे जीवागंज क्षेत्र में मंजू श्री साड़ी सेंटर के पास गौवंश का कटा हुआ सिर और एक पैर मिलने की सूचना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।

घटना की जानकारी मिलते ही विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और समाजजन बड़ी संख्या में माहेश्वरी धर्मशाला के ठीक सामने नयापुरा रोड पर एकत्रित हो गए और चक्का जाम कर सड़क पर बैठ गए। इसके चलते नयापुरा रोड पर आवागमन पूरी तरह ठप हो गया।

प्रशासन मौके पर, बातचीत जारी

बताया जा रहा है कि यह मार्ग पशुपतिनाथ मंदिर जाने का मुख्य रास्ता है, जिससे श्रद्धालुओं और आम लोगों को भारी परेशानी हो रही है। घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रशासनिक अमला तुरंत मौके पर पहुंचा। एडिशनल एसपी तेर सिंह बघेल स्वयं घटनास्थल पर मौजूद हैं। वे विश्व हिंदू परिषद के नेताओं व कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे हैं।

इलाके में पुलिस बल तैनात

चक्काजाम के चलते किसी भी व्यक्ति को इधर-उधर जाने नहीं दिया जा रहा है। मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया है। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। प्रदर्शनकारी दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं।

हैदरवास में भी मिले थे गौवंश के अवशेष

गौरतलब है कि इससे पहले 23 जनवरी को मंदसौर जिले के ग्राम हैदरवास में भी गौवंश के अवशेष मिलने पर तनाव की स्थिति बन गई थी। हैदरवास, मौजूदा घटनास्थल जीवागंज क्षेत्र से करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित है। कम दूरी के भीतर 13 दिनों में दो बार ऐसी घटनाएं सामने आने से आक्रोश और चिंता दोनों बढ़ गई हैं।

निगम के टैंकर की टक्कर से बुजुर्ग घायल

इंदौर। आजाद नगर इलाके में बुधवार दोपहर करीब 12 बजे नगर निगम के टैंकर की टक्कर से एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में टैंकर का पहिया बुजुर्ग के पैरों से गुजर गया, जिससे उनके दोनों पैर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। घटना के बाद टैंकर चालक मौके से फरार हो गया है, हालांकि पुलिस ने टैंकर को जब्त कर लिया है। चालक की तलाश की जा रही है। आजाद नगर थाना पुलिस के अनुसार यह दुर्घटना डेली कॉलेज के पास हुई। घायल की पहचान 85 वर्षीय सुंदरलाल पिता गंगादीन निवासी इदरीस नगर के रूप में हुई है। बताया गया कि सुंदरलाल रोज की तरह वॉकर लेकर पैदल घूमने निकले थे। वे घर से कुछ ही दूरी पर पहुंचे थे, तभी नगर निगम के टैंकर ने उन्हें तेज रफ्तार और लापरवाही से टक्कर मार दी। हादसे के दौरान टैंकर का पहिया सुंदरलाल के पैरों से गुजर गया, जिससे उनके दोनों पैर कट गए। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल उन्हें एमवाय अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। परिजनों का कहना है कि सुंदरलाल सड़क के बिल्कुल किनारे चल रहे थे और टैंकर चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए उन्हें टक्कर मारी। बताया गया है कि सुंदरलाल पहले पुलिसकर्मियों की दाढ़ी कटिंग का काम करते थे। उनके परिवार में तीन बेटे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

7वीं की बीमार छात्रा ने आत्महत्या की

इंदौर। आजाद नगर की 7वीं कक्षा की छात्रा ने आत्महत्या कर ली। घटना के समय वह घर पर अकेली थी। शाम को जब पिता घर पहुंचे, तो उन्होंने बेटी को फंदे पर लटका हुआ देखा। पुलिस ने मामला जांच में ले लिया है। आजाद नगर पुलिस के अनुसार, कृष्णापुरी कॉलोनी निवासी 13 वर्षीय प्राची ने अपने घर में फांसी लगाई। उसके पिता धर्मेंद्र ने बताया कि मंगलवार शाम को मैं घर पहुंचा था। उस समय दो छोटे बच्चे स्कूल से लौटने के बाद होटल चले गए थे। जब मैंने घर का गेट खोला तो अंदर प्राची फंदे पर लटकी हुई मिली। प्राची करीब एक महीने से तबीयत खराब होने के कारण स्कूल नहीं जा रही थी। दो दिन पहले ही उसने दोबारा स्कूल जाना शुरू किया था। आशंका है कि बीमारी या पढ़ाई के तनाव के चलते उसने यह कदम उठाया हो। प्राची के पिता चाय-नाश्ते की होटल संचालित करते हैं। प्राची का एक भाई और एक बहन है। पुलिस के मुताबिक, कमरे से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। मामले की जांच जारी है।

बुजुर्ग ने तनाव में आत्महत्या की

इंदौर। छत्रीपुरा इलाके में रहने वाले एक बुजुर्ग ने भी जहर खाकर जान दे दी। मंगलवार शाम उन्हें बेसुध हालत में एमवाय अस्पताल लाया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान रामजीवन (50) पिता रामनारायण, निवासी पंच मूर्ति नगर के रूप में हुई है। वह एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते थे। मंगलवार को उन्होंने जहर खा लिया था। परिजनों ने बताया कि उनसे काम नहीं हो पा रहा था, जिस कारण वे तनाव में रहते थे। उनकी तीन बेटियां हैं, जिनमें से एक की शादी हो चुकी है। काम और पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर वे परेशान थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

सिरपुर तालाब की जलकुंभी, अतिक्रमण हटाएं

इंदौर। शहर की महत्वपूर्ण रामसर साइट सिरपुर तालाब का निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने बुधवार को निरीक्षण किया। उन्होंने तालाब की वर्तमान स्थिति, चल रहे संरक्षण कार्यों और भविष्य की योजनाओं की जानकारी लेते हुए तालाब में फैली जलकुंभी हटाने, कैचमेंट एरिया को अतिक्रमण मुक्त करने, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए सिरपुर तालाब के प्रवेश द्वार पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने नागरिकों को तालाब में खाद्य सामग्री न डालने के लिए जागरूक करने और तालाब क्षेत्र, ग्रीन बेल्ट में अवैध कॉलोनी या अतिक्रमण रोकने के लिए सूचना बोर्ड लगाने को भी कहा। आयुक्त ने सिरपुर तालाब परिसर में स्थित इंटरप्रिटेशन सेंटर और 20 एमएलडी क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एसटीपी प्लांट में स्थापित स्काडा सिस्टम, लैब और संपूर्ण कार्यप्रणाली देखी। एसटीपी परिसर, आसपास व्यापक पौधारोपण करने तथा प्लांट से प्राप्त ट्रीटेड पानी का उपयोग ड्रिप सिंचाई के माध्यम से करने के निर्देश दिए।

बायपास पर चलती गाड़ी से चोरी की वारदात

इंदौर। लसूड़िया थाना क्षेत्र के बायपास पर शातिर बदमाश फिल्मी स्टाइल में खंडवा की ओर जा रहे लोडिंग वाहन से 18 बोरे पार्सल लेकर फरार हो गए। हैरानी की बात यह रही कि चालक को काफी देर तक चोरी की भनक तक नहीं लगी। फरियादी दिलशाद मंसूरी निवासी देवास, 2 फरवरी की रात 2.30 से 3.15 बजे के बीच वाहन (जीजे-23-एडब्ल्यू-4166) में डकाच्या से कुछ सामग्रियों से भरा पार्सल लेकर जा रहा था। जब वाहन फोनिक्स मॉल के पहले पहुंचा, तभी चालक को पीछे का दरवाजा हिलता दिखा। चालक ने तुरंत वाहन रोककर देखा तो उसके होश उड़ गए। बदमाश वाहन का ताला तोड़कर पार्सल ले गए थे। आशंका है कि आरोपी किसी अन्य वाहन से लोडिंग गाड़ी का पीछा कर रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोपियों की पहचान करने पुलिस बायपास पर लगे सीसीटीवी कैमरों और टोल नाकों के फुटेज खंगाल रही है। पुलिस को शक है कि इस वारदात के पीछे कोई संगठित गिरोह हो सकता है।

शिवरात्रि पर खिचड़ी बंटेगी, भोग लगेगा

इंदौर। महाशिवरात्रि पर खजराना गणेश मंदिर पर हजारों किलो साबूदाने की खिचड़ी का वितरण और खीर का भोग लगाया जाएगा। यह निर्देश मंदिर प्रशासक और कलेक्टर शिवम वर्मा ने समिति की बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि महाशिवरात्रि पर सुबह 9 बजे शिव महारुद्राभिषेक और आरती का आयोजन किया जाएगा। मंदिर और महाकाल मंदिर का श्रृंगार फूलों से किया जाएगा और विद्युत सज्जा से परिसर आकर्षक रूप में सजाया जाएगा। मंदिर परिसर में दानदाताओं और समाजसेवियों के सहयोग से सैकड़ों किलो प्रसादी का निर्माण किया जाएगा। बैठक में पार्किंग विस्तार, अन्न क्षेत्र विस्तार, पेयजल, सुरक्षा और सफाई व्यवस्था पर भी चर्चा की गई। साथ ही अन्न क्षेत्र में उपयोग होने वाले बर्तनों और परोसने वालों की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया गया।

तीन साल की अनिका को बचाएंगे स्कूल के बच्चे, 9 करोड़ के इंजेक्शन के लिए जुगत

अभी तक आधे पैसे साढ़े 4 करोड़ ही जुटे, अब उम्मीद स्कूल के बच्चों से

इंदौर। मालवा का ये ऐसा शहर है, जिसे आपसी जुड़ाव के लिए जाना जाता है। आपसी सामंजस्य और एक-दूसरे की मदद में इंदौर बेजोड़ है। इन दिनों यह शहर एक 3 साल की बच्ची अनिका का जीवन बचाने में लगा है। ये बच्ची 'स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी' (एसएमए) टाइप-2 नाम की दुर्लभ बीमारी से ग्रसित है। उसका जीवन बचाने के लिए 9 करोड़ के इंजेक्शन की जरूरत है। अब तक 4.5 करोड़ जुटे हैं। अब आखिरी उम्मीद बनकर सामने आया है एक अनोखा अभियान 'बच्ची को बचाएंगे बच्चे!' एक एनजीओ के साथ मिलकर अनिका के माता-पिता ने इंदौर के सभी स्कूलों से अपील की है कि अगर शहर के स्कूलों में पढ़ने वाले साढ़े चार लाख बच्चे सिर्फ 100-100 रुपये भी अनिका के लिए दान कर दें, तो बाकी बचे साढ़े चार करोड़ रुपये जुटाए जा सकते हैं। यह सिर्फ चंदा नहीं होगा, बल्कि बच्चों द्वारा एक बच्ची की जिंदगी बचाने का संकल्प होगा। आज अनिका की कहानी सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है। यह समाज की संवेदनशीलता, सामूहिक जिम्मेदारी और इंसानियत की परीक्षा है।

समय, पैसा और उम्मीद की दौड़

उसके माता-पिता अब तक 4.5 करोड़ जुटा चुके हैं। ये पैसा भी लोगों के सहयोग से इकट्ठा हुआ है। अब शहर के बच्चों से 100-100 रुपये की मदद मांगी गई है।

तीन साल की मासूम अनिका शर्मा शायद यह नहीं जानती कि उसकी मुस्कान के पीछे उसके माता-पिता रोज ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें समय, पैसा और उम्मीद तीनों एक साथ दौड़ रहे हैं। उनकी इकलौती संतान अनिका अति दुर्लभ बीमारी एसएमए टाइप-2 से पीड़ित है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (एसएमए) टाइप-2 एक आनुवंशिक विकार है जो 6-18 महीने के बच्चों में मांसपेशियों की गंभीर कमजोरी का कारण बनता है। यह रीढ़ की हड्डी के तंत्रिका कोशिकाओं को प्रभावित करता है। प्रभावित बच्चे बिना सहारे के बैठ सकते हैं, लेकिन वे चल या दौड़ नहीं सकते। इसके लिए जीन थेरेपी और सहायक उपचार उपलब्ध हैं।

क्राउडफंडिंग का सहारा

इस बीमारी का इलाज संभव है, लेकिन इसकी कीमत है पूरे 9 करोड़ रुपए का एक इंजेक्शन। इसके बाद अनिका सामान्य, स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ सकती है। बीते तीन-चार महीनों से अनिका के माता-पिता क्राउडफंडिंग के जरिए इस असंभव-सी लगने वाली राशि को जुटाने में लगे हैं। उन्होंने हर उस दरवाजे पर दस्तक दी, जहां से उम्मीद की एक किरण दिखी। चाहे वे नेता हों, उद्योगपति, व्यापारी, समाजसेवी या फिर नामी हस्तियां।

कई हस्तियों ने अपील की

गायिका पलक मुछाल और अभिनेता सोनू सूद जैसे लोगों ने अनिका के लिए आवाज उठाई। जब भारतीय क्रिकेट टीम मैच खेलने इंदौर आई, तब अनिका की मां ने कप्तान रोहित शर्मा से भी अपनी बच्ची की जिंदगी के लिए गुहार लगाई। इन तमाम कोशिशों और लाखों लोगों की मदद के बावजूद अब तक सिर्फ करीब 4.5 करोड़ रुपए ही जुटे हैं। मतलब की बच्ची के जीवन की मंजिल अभी आधी दूर है।

अनिका का वजन भी खतरा

कहानी की सबसे पीड़ादायक सच्चाई यहीं खत्म नहीं होती। अनिका के इलाज की एक और शर्त है, उसका वजन। डॉक्टरों के अनुसार, साढ़े 13 किलो वजन होने से पहले ही उसे यह इंजेक्शन लगना अनिवार्य है। उम्र के साथ वजन बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन अनिका के माता-पिता के लिए यही प्राकृतिक प्रक्रिया डर बन चुकी है। वे हर दिन यही दुआ करते हैं कि उनकी बच्ची का वजन धीरे-धीरे बढ़े, ताकि उन्हें थोड़ा और समय मिल सके। इस डर के कारण अनिका को आज वह खाना नहीं मिल पा रहा, जो हर बच्चे को मिलना चाहिए। उसे न रोटी मिलती है, न चावल सिर्फ जूस, दूध और फल दिए जा रहे हैं, ताकि उसका वजन नियंत्रित रहे। आज अनिका का वजन करीब साढ़े 10 किलो है। लेकिन, डॉक्टरों का कहना है कि एक से डेढ़ महीने में वह साढ़े 13 किलो तक पहुंच सकती है।

'अति उत्कृष्ट' एवं 'उत्कृष्ट सेवा' पदक से नवाजे जाएंगे इंदौर के 4 पुलिस वीर

प्रदेश के 269 अधिकारी और कर्मचारी इस सम्मान के लिए चुने गए

इंदौर। पुलिस सेवा में उत्कृष्टता का प्रतीक माने जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रतिष्ठित 'अति उत्कृष्ट सेवा पदक' और 'उत्कृष्ट सेवा पदक' से इस वर्ष मध्य प्रदेश के 269 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है। इनमें इंदौर नगरीय पुलिस के चार जांबाज भी शामिल हैं। इस सूची में एसीपी जूनी इंदौर विजय चौधरी, आरआई इंदौर दीपक कुमार पाटिल, निरीक्षक पंकज कुमार ताम्रकार और प्रधान आरक्षक (213) संतोष शर्मा शामिल हैं। इनके द्वारा कर्तव्य पालन में दिखाई गई निष्ठा और साहस ने न केवल व्यक्तिगत स्तर पर गौरव बढ़ाया, बल्कि पूरे इंदौर पुलिस महकमे का मान भी ऊंचा किया है। यह सम्मान केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा वार्षिक रूप से प्रदान किया जाता है, जो पुलिसकर्मियों के अपने कर्तव्य काल में किए गए असाधारण कार्यों के आधार पर दिया जाता है। वर्ष 2025 के लिए मध्य प्रदेश से कुल 123 पुलिसकर्मियों को 'अति उत्कृष्ट सेवा पदक' और 146 को 'उत्कृष्ट सेवा पदक' प्रदान किए गए। इंदौर के इन तीनों सम्मानित अधिकारियों का चयन राज्य पुलिस मुख्यालय द्वारा सावधानीपूर्वक प्रक्रिया के बाद किया गया, जिसमें उनकी 15 वर्ष से अधिक की बेदाग सेवा, कई पुरस्कार प्राप्ति और न्यूनतम दंड दर्ज होना प्रमुख मानदंड रहे।

सम्मानित पुलिसकर्मियों का योगदान

- एसीपी विजय चौधरी (जूनी इंदौर) : अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने में उनकी सक्रिय भूमिका ने जूनी इंदौर क्षेत्र को अपराध मुक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
- पंकज कुमार ताम्रकार : निरीक्षक (अ) पीए टू कमिश्नर को भी उनकी कर्तव्यनिष्ठा और कार्यक्षमता के लिए चुना गया।
- आरआई दीपक कुमार पाटिल (इंदौर) : जांच और अपराध अनुसंधान में उनकी कुशलता ने कई जटिल मामलों को सफलतापूर्वक सुलझाया, जिससे अपराधियों के खिलाफ मजबूत कार्रवाई संभव हुई।
- प्रधान आरक्षक संतोष शर्मा (2139) : सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन और सामुदायिक पुलिसिंग में उनके समर्पण ने आम नागरिकों का विश्वास जीता।

पुलिस मुख्यालय से चयनित नामों को केंद्रीय गृह मंत्रालय भेजा जाता है, जहां विशेषज्ञ समिति द्वारा गहन समीक्षा के बाद अंतिम स्वीकृति दी जाती है। यह पदक उन पुलिसकर्मियों को मिलता है, जिनकी सेवा अत्यंत सराहनीय हो और जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी इंसानियत का परिचय दिया हो। इंदौर पुलिस आयुक्त ने इन सम्मानों पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि यह उपलब्धि पूरे महकमे के लिए प्रेरणादायक है। यह सम्मान न केवल व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि मध्य प्रदेश पुलिस की समग्र उत्कृष्टता को दर्शाता है। इंदौर वासियों ने भी सोशल मीडिया पर इन पुलिसकर्मियों को बधाई दी, जो शहर की कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने वाले सच्चे सिपाहियों के रूप में उभरे हैं।

इंदौर जिले के 9% जल स्रोत दूषित देपालपुर की स्थिति सबसे खराब

20 दिन में भागीरथपुरा में गंदे पानी की 1851 शिकायतें

इंदौर। शहर के भागीरथपुरा इलाके में हुई दूषित जल त्रासदी से अभी तक 32 मौतें हो चुकी। इसके बाद भी दूषित जल से शहर को मुक्ति नहीं मिल रही। यह त्रासदी सिर्फ शहर तक सीमित नहीं है। इंदौर के अलावा महू, देपालपुर और सांवेर ब्लॉक में भी पेयजल प्रदूषित पाया गया। पानी के 566 सैंपलों की जांच में 51 फेल हुए। लिए गए सैंपल से 9 प्रतिशत जल स्रोत ऐसे हैं, जिनका पानी पीने योग्य नहीं मिला। देपालपुर की स्थिति सबसे खराब पाई गई। सैंपलों की जांच में सबसे ज्यादा दूषित पानी 32 प्रतिशत देपालपुर ब्लॉक में मिला। सांवेर में 11.49 प्रतिशत, महू में 5.77 प्रतिशत और इंदौर ब्लॉक में यह 4.14 प्रतिशत रहा। आंकड़ों के मुताबिक जिले में जो सर्वे हुआ है, उसमें 42 नल-जल योजनाएं बंद हैं। इसमें राऊ विधानसभा क्षेत्र में 4, सांवेर में 20, देपालपुर में 8, महू में 10 योजनाएं शामिल हैं।

पुरानी लाइनें सुधारेंगे - प्रदेश भर में स्वच्छ जल अभियान का पहला चरण चल रहा है जो 28 फरवरी तक चलेगा। इसमें सर्वे सहित जल स्रोत की पहचान करना है। 1 मार्च से दूसरा चरण शुरू होगा जो 31 मई तक चलेगा। एसओपी के तहत 20 साल से अधिक पुरानी लाइनों को चिह्नित कर 48 घंटे में लीकेज की मरम्मत करेंगे।

जल अभियान में इन पर ध्यान

भागीरथपुरा मामले के बाद 13 जनवरी से हर मंगलवार को जिले में जल-सुनवाई हो रही है। इसमें दूषित पानी सहित अन्य दिक्कतों की अब तक 1851 शिकायतें आईं। तय किया गया कि जल आपूर्ति से संबंधित शिकायतों को इमरजेंसी कैटेगरी में रखना होगा। सीएम हेल्पलाइन में गंदे पानी तथा सीवेज की शिकायतों को तुरंत हल करेंगे। पीएचई की जल परीक्षण लैब से जल नमूनों का नियमित अंतराल पर परीक्षण होगा। शहरी क्षेत्रों में सुरक्षित एवं निर्बाध पेयजल आपूर्ति के लिए सर्वे किया जाएगा। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और ओवरहेड टैंक, संपवेल की सफाई 7 दिन के अंदर। बीआईएस 10500 में सीमा से अधिक प्रदूषण होने पर जलापूर्ति को रोकेंगे। साथ ही जल गुणवत्ता एवं जल जनित बीमारियों के संबंध में एडवाइजरी जारी होगी।

मूक-बधिर युवती से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत निरस्त की

हाई कोर्ट ने जिला कोर्ट का जमानत का आदेश पलटा

इंदौर। मूक-बधिर युवती से दुष्कर्म के गंभीर मामले में जिला कोर्ट के आदेश को पलटते हुए हाई कोर्ट ने आरोपी की जमानत निरस्त कर दी। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सहमति से या बिना सहमति के अपराध हुआ, यह ट्रायल का विषय है। ऐसे में आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती। पीड़िता की ओर से जमानत निरस्त करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने जिला कोर्ट द्वारा दी गई जमानत को रद्द कर दिया।

पीड़िता की एडवोकेट शन्नो शगुफ्ता खान ने बताया कि 18 साल की मूक-बधिर युवती से 4 अप्रैल 2025 को दो युवकों ने दुष्कर्म किया। दोनों आरोपी युवती को सुबह करीब 10 बजे जबरन घर से उठा ले गए थे और वारदात के बाद उसे घर पर छोड़ दिया। घटना के दौरान युवती के परिजनों ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। बाद में घर लौटने पर युवती ने सांकेतिक भाषा में परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा आरोपी फरार हो गया था। एडवोकेट ने बताया कि पीड़िता 50 प्रतिशत मंदबुद्धि भी है। इसके बावजूद घटना के करीब दो माह बाद जिला कोर्ट ने आरोपी को यह कहते हुए जमानत दे दी थी कि युवती को सहमति से ले जाया गया था या बिना सहमति के यह साक्ष्य का विषय है। जिला कोर्ट के इस आदेश का विरोध करते हुए पीड़ित पक्ष ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला कोर्ट के जमानत आदेश को निरस्त कर दिया।

'लव जिहाद' के लिए पैसा देने वाले 26 केस के आरोपी कादरी की हाईकोर्ट से जमानत

सह-आरोपियों की जमानत हुई, इस आधार पर मिली हाईकोर्ट से जमानत

इंदौर। वार्ड-58 से कांग्रेस पार्षद रहे अनवर कादरी को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। उन पर लव जिहाद के लिए फंडिंग करने का आरोप है। इसके अलावा एक दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामलों में भी उन्हें आरोपी पाया गया। जिला कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद कादरी ने हाईकोर्ट में अपील की थी, जिसे 4 फरवरी को मंजूर कर लिया गया। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की बेंच ने सुनवाई के बाद याचिका स्वीकार की है। यह मामला बाणगंगा थाना क्षेत्र का है। जून 2025 में एक युवती ने साहिल शेख और अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। युवती का आरोप था कि साहिल ने प्रेम जाल में फंसाकर उसका शारीरिक शोषण किया और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। बुर्का पहनने के लिए भी मजबूर किया गया। जांच के दौरान साहिल शेख ने बयान दिया कि इस तरह के मामलों के लिए अनवर कादरी के जरिए दो लाख रुपए की फंडिंग की जाती थी। इसके बाद पुलिस ने कादरी को मुख्य आरोपी बनाते हुए विभिन्न गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया। केस दर्ज होने के बाद अनवर कादरी फरार हो गया था। लंबे समय बाद उसने कोर्ट में सरेंडर किया, जिसके बाद से वह जेल में बंद था।

कादरी पर मामलों का रिकॉर्ड

अनवर कादरी पर एक दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें डकैती सहित कई गंभीर अपराध शामिल हैं। डकैती के मामलों के चलते ही उसकी पहचान 'अनवर डकैत' के नाम से बनी। लव जिहाद केस सामने आने के बाद महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने संभाग आयुक्त को पत्र लिखकर कादरी की पार्षदी समाप्त करने की सिफारिश की थी। इसके बाद निगम परिषद में प्रस्ताव पास कर उसकी पार्षदी खत्म की गई। संभागायुक्त डॉ सुदाम पी खाड़े ने भी कादरी को पार्षद पद से हटाते हुए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था।

जिला कोर्ट ने जमानत नहीं दी

अनवर कादरी ने पहले जिला कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी, जिसे 10 दिसंबर 2025 को खारिज कर दिया गया था। कादरी का तर्क था कि सह-आरोपी साहिल और अन्य को हाईकोर्ट व जिला कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, इसलिए उसे भी राहत दी जाए। इस पर जिला कोर्ट ने कहा था कि कादरी पर फंडिंग के आरोप हैं, वह मुख्य आरोपी है, इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती। जबकि, हाईकोर्ट में भी कादरी ने यही दलील दी कि सभी सह-आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। इन्हीं आधार पर हाईकोर्ट ने जमानत याचिका मंजूर की है।

गंभीर धाराओं में प्रकरण

अनवर कादरी के खिलाफ विभिन्न धाराएं जैसे- धारा-323, 506, 392, 324, 25 आर्म्स एक्ट, 302, 307, 452, 341, 427, 64, 64(2)(एम), धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम सहित कई अन्य आपराधिक धाराओं में गंभीर प्रकरण पंजीबद्ध हैं। इन धाराओं के अलावा भी पार्षद अनवर कादरी पर अनेक धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। पार्षद अनवर कादरी पर गंभीर आरोप लगे हैं।

मामला जून 2025 का है, जब एक वीडियो सामने आया था, जिसमें दो युवकों ने हैरान करने वाला खुलासा किया था। उनका कहना था कि कादरी ने उन्हें पैसे दिए थे ताकि वे हिंदू महिलाओं को अपने जाल में फंसा कर धर्म परिवर्तन और वेश्यावृत्ति की ओर धकेलें।

तीन महीने फरार रहा

वीडियो वायरल होते ही हड़कंप मच गया था। पुलिस ने फौरन मामला दर्ज कर लिया था। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में कुछ माह पहले दो युवकों पर दो युवतियों के साथ रेप और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान सामने आए वीडियो में दोनों आरोपियों ने कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी का नाम लिया। जिस पर उन्हें लड़कियों को प्रेमजाल में फंसाने और निकाह के लिए पैसों का लालच देने का आरोप है। पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। कादरी तब फरार हो गया थे। पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए इंदौर, दिल्ली समेत कई शहरों में दबिश दी। उनकी गिरफ्तारी पर 40 हजार रुपए का इनाम रखा था। इसी दौरान उनकी बेटी आयशा को भी गिरफ्तार किया गया। उस पर पिता को छिपाने में मदद करने का आरोप लगा था। तीन महीने फरार रहने के बाद 29 अगस्त को कादरी ने जिला अदालत में सरेंडर किया था।

संपादकीय

मणिपुर: क्या शांति लौटेगी?

अशांत पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में करीब एक साल के राष्ट्रपति शासन के बाद भाजपा ने फिर से सरकार बनाई है और वरिष्ठ तथा अपेक्षाकृत उदारवादी नेता युमनाम खेमचंद सिंह को नया मुख्यमंत्री बनाया है। सिंह को राज्यपाल अजय भल्ला ने पद की शपथ दिलाई। इससे पहले 62 वर्षीय खेमचंद सिंह को नई दिल्ली में हुई बैठक में भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया था। मार्शल आर्ट के धुरंधर और मैतेई समुदाय के युमनाम खेमचंद सिंह के साथ कुकी समुदाय की विधायक नेम्चा किपजेन तथा नगा पीपुल्स फ्रंट के विधायक एल दिखो ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसी के साथ राज्य में राष्ट्रपति शासन समाप्त हो गया है। बताया जाता है कि पूर्व मुख्यमंत्री बीरेन सिंह अपने समर्थक गोविंददास को सीएम बनाना चाहते थे, लेकिन विधायक दल में खेमचंद के नाम पर सहमति बनी। मणिपुर में अगले साल मार्च में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में नए सीएम के सामने सबसे बड़ी चुनौती मैतेई बनाम कुकी संघर्ष के बीच ऐसा संतुलन साधना है, जिससे विधानसभा चुनाव में भाजपा को नुकसान न हो। भाजपा चाहती है कि आगामी चुनाव से पहले मणिपुर में जमीनी स्तर पर शांति बहाली हो। गौरतलब है कि मणिपुर में मई 2023 में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच भड़की जातीय हिंसा पर अब तक विराम नहीं लग सका है। राज्य में कुकी और मैतेई समाज और भौगोलिक खाइयां इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि दोनों समुदाय एक-दूसरे के खून के प्यासे हैं। तमाम कोशिशों के बाद भी इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। कुकी अब मैतेइयों के साथ नहीं रहना चाहते हैं। लेकिन मणिपुर की भौगोलिक स्थिति और जनजातियों की बसाहट ऐसी है कि राज्य का विभाजन संभव ही नहीं है। मैतेई ज्यादातर इंफाल घाटी में रहते हैं और कुकी एवं नगा जंगलों में रहते हैं। इंफाल घाटी पहाड़ों और जंगलों से घिरी हुई है। खेमचंद के सीएम बनने से मणिपुर में हालात सुधरेंगे, कितने सुधरेंगे, यह बड़ा सवाल है। हालांकि सीएम खेमचंद ने शपथ ग्रहण के बाद एक कुकी बच्चे को गोद में उठाकर सौहार्दपूर्ण संदेश देने की कोशिश जरूर की है। लेकिन राज्य में शांति स्थापना और सरकार बहाली की इन कोशिशों को पहला झटका कुकी जो काउंसिल ने दिया है। काउंसिल ने कहा है कि यदि कोई कुकी विधायक सरकार में शामिल होता है तो यह उसका व्यक्तिगत फैसला होगा। काउंसिल के मुताबिक कुकी जो समुदाय मणिपुर सरकार के गठन में भाग नहीं लेगा। यह फैसला सभी जनजातियों, शीर्ष संगठनों और क्षेत्रीय संस्थाओं ने मिलकर लिया है। ऐसे में सीएम खेमचंद दोनों समुदायों के बीच अविश्वास की खाई को कितना पाट पाएंगे, यह बड़ा सवाल है। गौरतलब है कि मणिपुर में अलगाववादी विद्रोही संगठन तो पहले ही से सक्रिय थे, लेकिन तीन साल पहले राज्य में मैतेइयों को भी आदिवासी मानने के कोर्ट के फैसले ने राज्य में सामुदायिक विभाजन की आग सुलगा दी, जो बुझाए नहीं बुझ रही है। इसके अलावा अगले साल मणिपुर में विधानसभा चुनाव है। राज्य में कुल 60 सीटें हैं, जिसमें 2022 के चुनाव में बीजेपी ने 32 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। बाद में जेडीयू के 5 विधायक भी भाजपा में शामिल हो गए थे। विधानसभा चुनाव में अभी एक साल है, लेकिन तब तक मणिपुर में हालात कितने सामान्य होंगे, कहना मुश्किल है। क्योंकि मैतेई कुकी विवाद के पीछे एक धार्मिक कारक भी काम कर रहा है। मैतेई ज्यादातर हिंदू हैं और कुकी एवं नगा ईसाई हैं। कुकी अपना प्रदेश अलग चाहते हैं और इसमें परोक्ष रूप से ईसाई मिशनरियों का हाथ भी बताया जाता है। बीते तीन साल में राज्य में भारी खून-खराबा, लूटपाट और हिंसा हो चुकी है। ऐसे में शांति बहाली बहुत बड़ी चुनौती है।

गरिमा की रक्षा हेतु एआई युग में मानव अधिकार शिक्षा जरूरी

नज़रिया

प्रो. कन्हैया त्रिपाठी
लेखक राष्ट्रपति जी के विशेष कार्य अधिकारी रह चुके हैं। एनएचआरसी (इंडिया) में सीनियर मॉनिटर व केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब में चेयर प्रोफेसर हैं।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानि कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े दुनिया के नीतिशास्त्री, भविष्य को सुरक्षित रखने वाले दार्शनिक सामाजिक बहस की मांग उठा रहे हैं। एआई यूजर्स भले ही धड़ल्ले से इसका सहारा लेने में संकोच नहीं कर रहे हैं लेकिन बड़े विशेषज्ञ व वैज्ञानिकों को अपने अस्तित्व का डर सताने लगा है। आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डोर किसके हाथ में होगी, यह सबकी चिंता है। वस्तुतः यह दावा किया गया कि अल्गोरिद्म आधारित एआई सिस्टम, मनुसिब प्रशिक्षण सामग्री के बिना टेक्स्ट, छवियां या संगीत अभी भी नहीं तैयार कर सकते हैं। किन्तु सीखने की कला यानि लर्निंग सिस्टम को जरूरी डाटा मुहैया कराने के लिए, डेवलपर यह पूछे बिना, सहमति लिए बिना और मुआवजा दिए बिना, बहुतेरे काम कर रहे हैं और एआई का इस्तेमाल करते हैं। विशेषज्ञ यह मानते हैं कि हमारी कीमत पर ये सेल्फ-सर्विस हमें स्वीकार्य नहीं है। यह तो एक प्रकार से निजता का हनन है।

अब ज़रूरी है कि क्षमता निर्माण कार्यक्रम शिक्षा के अधिकार और मानवाधिकारों की प्राप्ति को प्रभावित करने वाली उभरती वैश्विक चुनौतियों की जांच हो। जागरूकता बढ़ाने और उनका समाधान करने के तंत्र के व्यापक अधिदेश हैं। आज जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता-एआई की भूमिका सभी क्षेत्रों में बढ़ रही है, तब विकास, आर्थिक प्रगति को बड़े पैमाने पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि, यह आसानी से उपलब्ध डेटा, बढ़ते डिजिटलीकरण, पूंजी प्रवाह और एआई के उपयोग से दक्षता लाभ द्वारा संचालित है। एआई का प्रभाव विविध और व्यापक है, और यह कई हितधारकों-राज्य, व्यवसाय, उपभोक्ताओं और कार्यबल को प्रभावित कर रहा है। यहाँ तक कि शैक्षिक प्रणाली एआई से प्रभावित है, और शिक्षार्थियों को कार्यस्थल में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके भी कई प्रमाण सामने आए हैं। सबसे बड़ी बात इसके द्वारा कई मानवाधिकार उल्लंघन भी हैं। मानवाधिकारों को प्रभावित करने वाली विकासशील वैश्विक गतिशीलता, विशेष रूप से तीव्र तकनीकी परिवर्तन से जुड़ी गतिशीलता के आलोक में अधिकारों के व्यापक ढाँचे में सांस्कृतिक अधिकारों पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभावों का विशेष रूप से अन्वेषण होना इसलिए ज़रूरी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाली प्रौद्योगिकियाँ पहले से ही सांस्कृतिक परिदृश्य को नया रूप दे रही हैं यहाँ तक कि रचनात्मक उत्पादन और प्रसार से लेकर सांस्कृतिक सामग्री की सुलभता, भाषा संरक्षण और सांस्कृतिक जीवन में भागीदारी तक। साथ ही, ये विकास कई

महत्वपूर्ण जोखिमों को जन्म देते हैं, जिनमें दुष्प्रचार, एल्गोरिथम संबंधी पूर्वाग्रह, शैक्षिक तंत्र और सांस्कृतिक विविधता का क्षरण शामिल हैं, जो लगातार डिजिटल विभाजनों से और बढ़ रहे हैं।

एआई का विकास और उपयोग विकास के अधिकार के अनुरूप हो, इसको किसी को चिंता आज नहीं है। शिक्षा के साथ एआई का हस्तक्षेप बढ़ने पर एक शिक्षक के अधिकार-आधारित दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो सांस्कृतिक आत्मनिर्णय और शैक्षिक एवं सांस्कृतिक जीवन में भागीदारी को मान्यता प्रदान करे और उसकी रक्षा करे। हालाँकि, तीव्र तकनीकी प्रगति की पृष्ठभूमि में, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर खंडित और अपर्याप्त विनियमन सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्षम नहीं लगती हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाजों और शिक्षा जगत को नया आकार दे रही है और हमारे जीने, सीखने और परस्पर क्रिया करने के तरीके को बदल रही है। अब यह महसूस किया जा रहा है कि जहाँ एक ओर एआई शैक्षिक प्रणालियों को बेहतर बनाने और ज्ञान तक पहुँच को लोकतांत्रिक बनाने की अपार क्षमता प्रदान कर रही है, वहीं यह नैतिकता, पूर्वाग्रह, जवाबदेही और मानवाधिकारों से जुड़े गंभीर प्रश्न भी है। शैक्षणिक संस्थानों और हितधारकों को न केवल आज तकनीकी जानकारी से लैस होना चाहिए, बल्कि एआई के उपयोग से जुड़े जोखिमों का आकलन और उन्हें कम करने के ढाँचों से भी लैस होना चाहिए, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में।

भारत के मानव अधिकारों की छवि, आम तौर पर अच्छी है, हालांकि कुछ गैर-सरकारी संगठनों ने कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन को एक मुद्दा बनाया है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। पश्चिमी देश मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण पर किसी भी प्रतिबंध के धर्म की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध मानते हैं, जो उनके विचारकों द्वारा बनाए गए धर्म की स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रेटिंग को कम करता है।

यह सुनिश्चित करने के वैश्विक प्रयासों के साथ कि एआई का विकास और उपयोग अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों और समता के सिद्धांतों के अनुरूप हो, शिक्षकों, नीति निर्माताओं, प्रौद्योगिकीविदों, अन्य हितधारकों और नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं के बीच क्षमता निर्माण की सख्त आवश्यकता है। शैक्षिक नवाचार और मानवाधिकारों के अंतर्संबंधों का अन्वेषण होना चाहिए। विगत कुछ समय पहले भारत सरकार ने देश में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस को बढ़ावा देने के लिए एक नए मिशन को मंजूरी दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने इंडिया एआई मिशन के लिए 10,371 करोड़ रुपये के बजट को मंजूर किया। सरकार का कहना है कि इस मिशन के तहत एआई को जिम्मेदार तरीके से डेवेलप करने और अपनाने पर जोर होगा। एक नेशनल डाटा मैनेजमेंट दफ्तर बनाया जाएगा, जो सरकारी विभागों के साथ मिलकर यह देखेगा कि एआई के विकास के लिए गैर निजी डाटा किस तरह उपलब्ध कराया जा सकता है। किन्तु संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने कृत्रिम बुद्धिमता-एआई के ज़रिए तैयार की जा रही बच्चों की यौन तस्वीरों, उन्हें साझा किए जाने के मामलों में आए तेज़ उछाल पर गहरी चिन्ता जताई है। इस पर लगाम कसने के लिए ठोस सुरक्षा उपायों की मांग की गयी है। इनमें बड़ी संख्या में ऐसे मामले भी हैं, जिनमें बच्चों की तस्वीरों में छेड़छाड़ के ज़रिए उन्हें यौन रूप-सेक्सुअलाइज्ड ही पेश किया गया। यह सब पढ़ा-लिखा समाज कर रहा है। हाँ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने दुनिया को तेज़ी से बदल दिया ज़रूर। स्व-चालित वाहन, चिकित्सीय इमेज का विश्लेषण, व्यवसायों के लिए सामान का प्रबंधन, वित्तीय कारोबार ऐल्गोरिदम, वर्चुअल सहायता और बिना कोई देरी किए भाषा अनुवाद जैसी चीज़ों में एआई का असर साफ़ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब जब इसकी चुनौतियाँ हमारे सामने खड़ी हो रही हैं और वैश्विक स्तर पर आमजन के मानव अधिकारों के हनन की बातें उठ रही हैं तो शिक्षा जगत में एआई के भावी दुष्परिणामों से भी निपटने की पूरी तैयारी ज़रूरी है।

देश के सभी स्कूल्स, कॉलेज, विश्वविद्यालय व शैक्षणिक संस्थानों के साथ शिक्षा जगत से जुड़े लोगों का दायित्व है की वे कई चौकाने वाली चुनौतियों को चिन्हित करें। यह सुनिश्चित करें कि देश में शिक्षा व मानव अधिकार के मुद्दे को समझें। जेंडर आधारित मसले भी हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उच्च शिक्षा से जुड़े लोगों का है कि वे मानव अधिकारों के संरक्षण पर कार्य करें। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नए संस्करणों के साथ हमारे मानव अधिकारों की सुरक्षा यदि हम नहीं कर सकेंगे तो सभी को समस्याओं को झेलने के लिए तैयार रहना होगा। मानव अधिकार शिक्षा इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में हम बचाव के बारे में जागरुक हों। विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़ी लीडरशिप की यह जिम्मेदारी है कि वे अपने कैम्पस में एक अच्छा माइंडसेट डेवलप करें जो नेशन बिल्डिंग के लिए काम आए और लोगों की गरिमा भी सुरक्षित व प्रतिष्ठित रहे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा है कि उचित नियमों के बिना, एआई असमानताओं और डिजिटल विभाजन को और बढ़ा सकती है और सबसे कमज़ोर वर्गों को असमान रूप से प्रभावित कर सकती है। हमें इस समय को समझना चाहिए ताकि यह मानवता के लिए लाभकारी हो।

चुनौतियों का जवाब देने वाला बजट 2026

प्रतिक्रिया

अवधेश कुमार
लेखक दिल्ली निवासी वरिष्ठ पत्रकार हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक महिला के रूप में और लगातार नौ बजट पेश करके रिकॉर्ड बनाया है। हमारे आपके लिए महत्वपूर्ण यह है कि उनके द्वारा प्रस्तुत बजट भारत के सभी समूहों की आकांक्षाओं, आंतरिक और बाह्य चुनौतियों व आवश्यकताओं, राजनीतिक मांग एवं नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा देश के घोषित आर्थिक विकास लक्ष्यों की कसौटी पर खरा है या नहीं? पिछले कुछ समय से उत्पन्न वैश्विक उथल-पुथल में भारत को अपनी विकास गति बनाए रखने के साथ नए वैश्विक साझेदारी,निर्यात बाजार आदि विकसित करने तथा घरेलू उत्पादकों को नीतियों और प्रोत्साहन से समर्थन देने तथा सबके साथ समाज के निचले तबके से लेकर हर समूह की चाहत के बीच सामंजस्य बिठाने की चुनौती है। आर्थिक सर्वेक्षण में साफ कहा गया था कि वैश्विक उथल-पुथल जल्दी समाप्त नहीं होने वाला इसलिए भारत को मैराथन एवं स्प्रिंट दोनों दौड़ लगाने की आवश्यकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 53.47 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट पेश कर यह संदेश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार इन चुनौतियों और संकटों को अवसर में बदलने की दृष्टि से काम कर रही है। कोई लोक लुभावन घोषणा नहीं पूरा फोकस इस बात पर कि इस उथल-पुथल और अनिश्चितताओं के दौर में देश की अर्थव्यवस्था सुरक्षित, मजबूत और स्थिर होने के साथ विस्तारित भी हो, विश्व व्यापार के अनुरूप पर्याप्त गुणवत्तापूर्ण उत्पादन हो, किशोर और युवा वर्ग को भारत राष्ट्र के लक्ष्य और रोजगार दिलाने के अनुरुप शिक्षा, रोजगार के अवसर के साथ समाज के सभी समूह के लोगों का जीवन सुरक्षित हो सहज हो तथा आवश्यक सेवाएं सहायक उपलब्ध हों ...।

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में तीन कर्तव्य के नाम पर लक्ष्य और बजट की सैद्धांतिक आधारभूमि स्पष्ट कर दिया। पहला, उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने तथा वैश्विक उथल-पुथल के परिदृश्य में लचीलापन लाकर आर्थिक विकास को तेज करना और उसकी गति बनाए रखना। दूसरा, भारत की समृद्धि के पथ में सशक्त साझेदार बनाने के लिए लोगों की आकांक्षाएं पूरी करना और उनकी क्षमता बढ़ाना। तथा तीसरा, सरकार की सबका साथ, सबका विकास के दृष्टिकोण के अनुकूल- यह सुनिश्चित करना कि सार्थक भागीदारी के लिए प्रत्येक परिवार, समुदाय और क्षेत्र की संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों तक पहुंच उपलब्ध हो। प्रधानमंत्री ने स्वयं अपने भाषणों में व्यापक सुधारो का संकेत दिया था। वित्त मंत्री ने कहा कि हम 12 साल से आर्थिक विकास की दिशा में काम कर रहे हैं और आर्थिक सुधार की गाड़ी सही रास्ते पर है, 350 से अधिक सुधार किए हैं और अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए इसकी गति बनाए रखनी पड़ेगी। उन्होंने आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए सात क्षेत्रों में पहल शुरू करने का प्रस्ताव रखा- रणनीतिक और अग्रणी क्षेत्रों में विनिर्माण को तेज करना। दो, विरासत के औद्योगिक क्षेत्रों का कायाकल्प करना। तीन, चैंपियन एमएसएमई का निर्माण करना। चार, आधारभूत संरचना को सशक्त प्रोत्साहन प्रदान करना। पांच, दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और स्थायित्व सुनिश्चित करना। सात, शहरों में आर्थिक क्षेत्र विकसित करना...। आप देखेंगे कि अपनी सैद्धांतिक आधारों और इन प्रक्रियाओं की दृष्टि से बजट में व्यवहारिक साहसिक और विजनरी घोषणायें हैं।

तमाम उथल-पुथल के बीच नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा अपने राजकोषीय अनुशासन को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। घोषित लक्ष्यों के अनुरुप राजकोषीय घाटा 4.4% तक सीमित रखना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इसीलिए इस वर्ष के लिए 4.3% का लक्ष्य घोषित किया गया है। कर राजस्व में थोड़ी कमी है लेकिन ऐसी नहीं जिससे योजनाओं की दृष्टि से आवंटन में समस्याएं आयें। पूंजीगत खर्च जो मुख्ता आधारभूत संरचना पर खर्च होता है के लिए 12 लाख 20 करोड़ का आवंटन सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करता है। यह कुल बजट का लगभग 23% है। यूपीए सरकार में कभी भी पूंजीगत ब्याज 7-8% से ज्यादा नहीं गया। यहीं पर सरकार की विचारधारा नीति और दुर्गा में सोच स्पष्ट होता है कि आपका सबसे ज्यादा फोकस किस बात पर है। यानी भारत को हर क्षेत्र में कृषि से लेकर कुटीर उद्योग, ग्रामीण उद्योग, कपड़ा, हस्तकरघा, वाहन, यातायात, सूचना तकनीक.... सभी क्षेत्र की आधारसंरचना इतनी सशक्त और विकास के अनुकूल बना दिया जाए कि आने वाले वर्षों तक इन पर आर्थिक गतिविधियां खिलखिलाती मुस्कुराती तेज गति से बढ़ती रहे।

कुछ और पहलुओं पर नजर दौड़ायें । विनिर्माण, सेवा और कृषि हमारी अर्थव्यवस्था और विकास के मूलाधार हैं। कुशल और दक्ष युवा वर्ग तैयार करना भारत का बड़ा लक्ष्य है,क्योंकि जब हम यूरोपीय संघ और अन्य देशों से मोबिलिटी समझौता करते हैं तो काम करने वालों के क्षेत्र का भौगोलिक विस्तार हो जाता है। बजट में शिक्षा से रोजगार और उद्यमिता के नाम से एक स्थायी उच्चाधिकार समिति का गठन होगा जो सेवा क्षेत्र को विकसित भारत का मुख्य चालाक बनने के लिए आवश्यक उपायों की अनुशंसा करेगा। 2047 तक भारत का सेवा क्षेत्र में वैश्विक हिस्सा 10 प्रतिशत तक ले जाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निश्चित है। यह स्थायी समिति वृद्धि, रोजगार और निर्यात की संभावनाओं को अधिकतम करने वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता देगी। आप सोचिए दुनिया भर का जो सेवा क्षेत्र है उसमें हमारा योगदान कम से कम एक दही हो इसकी दृष्टि से ही नहीं भारत दूसरे छात्रों में भी भारत और विश्व की आवश्यकताओं के अनुकूल कुशल कार्यबल तैयार करने का एक स्थायी ढांचा तैयार किया जा रहा है ।उभरती तकनीकों, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, का नौकरियों और स्किल पर प्रभाव आंकेगी और आवश्यक नीतिगत उपाय सुझाएगी। स्वास्थ्य पेशेवर बनाने वाले संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा जिसमें रेडियोलॉजी, एनेस्थीशिया जैसे क्षेत्रों पर फोकस होगा। अगले पांच वर्ष में एक लाख एएचपी जोड़े जाएंगे तो 1.5 लाख केयर गिवर्स को प्रशिक्षित किया जाएगा।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, मुम्बई को 15 हजार माध्यमिक विद्यालयों और पांच सौ महाविद्यालयों में ए.वी.जी.सी. कंटेंट क्रिएटर लैब (सी.सी.एल.) स्थापित करने में सहायता प्रदान किया जाएगा। आधुनिक समय में औरेंज इकोनामी दृष्टि से स्टोरी टेलिंग को क्रिएटिव आर्ट से मिलाने व गेमिंग, एनीमेशन आदि क्षेत्र का स्किल विकसित किया जाएगा। वैश्विक बायोफॉर्मा निर्माण केन्द्र के रूप में भारत को विकसित करने के लिए कुल 10,000 करोड़ रुपये से बायोफॉर्मा शक्ति की शुरुआत हो रही है जो बायोलॉजिक और बायोसिमिलरों के घरेलू उत्पादन के लिए अगले पांच वर्षों में इको-सिस्टम का निर्माण करेगी। इसकी रणनीति में तीन नए राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर) और सात वर्तमान संस्थानों के उन्नयन के साथ बायोफॉर्मा पर केन्द्रित नेटवर्क बनाया जाएगा। यह 1000 मान्यता प्राप्त भारत क्लिनिक जांच स्थलों के एक नेटवर्क का निर्माण करेगा। सेमीकंडक्टर और एआई क्षेत्र में देर से आने के बावजूद अग्रणी देश बनने की दृष्टि से महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। रेयर अर्थ मिनिरल्स अन्य दुर्लभ खनिज संसाधन की संपूर्ण दुनिया में मांग है और चीन 94% बाजार पर हिस्सा रखता है। हमें भी जब चाहता है तभी देता है । घरेलू कैपिटल-गुड्स क्षमताएं बनाने और एक स्वतंत्र आपूर्ति श्रृंखला खड़ा करने का लक्ष्य बनाया गया है। इसके लिए ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल जैसे खनिज-समृद्ध राज्यों में दुर्लभ पृथ्वी संसाधनों की खोज, खुदाई और संसाधन की श्रृंखला बनेगी।

थल, जल और नभ यातायात में भारत वैसे ही दुनिया के अनेक देशों को पीछे छोड़ चुका है। एक बड़ा फोकस इस समय जल यातायात है। पर्यावरण रूप से टिकाऊ आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए पूर्वी भारत में डानकूनी से पश्चिमी भारत के सूरत को जोड़ने के लिए नए समर्पित माल गलियारे, पांच वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्गों (एनडब्ल्यू) का संचालन , जलमार्गों और तटीय पोत परिहवन की हिस्सेदारी 6 प्रतिशत से बढ़ाकर वर्ष 2047 तक 12 प्रतिशत करने के लिए तटीय कार्गोनन, सात उच्च-गति रेल कॉरीडोर विकसित करना, सी-प्लेन के स्वदेशी निर्माण के लिए प्रोत्साहन के लिए योजना आदि। इनके साकार होने के बाद कल्पना करिए कि भारत विश्व स्तरीय यातायात में कहां खड़ा होगा और यह हमारे आम जीवन से लेकर आंतरिक और विदेशी आर्थिक क्रियाकलापों के लिए कितनी बड़ी आधारभूमि होगी। तो कुल मिलाकर 2047 के विकसित भारत का लक्ष्य पाने और फिर उसके आगे सतत छलांग लगाते रहने की दृष्टि से वर्तमान एवं दूरगामी भविष्य के संभावित आवश्यकता है और चुनौतियों की दृष्टि से बजट समग्र दृष्टिकोण और योजना प्रस्तुत करती है।

शीतकालीन बजट में महँगा होता प्यार

कटाक्ष

अंशु प्रधान
लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

इंसान की ज़िंदगी में बजट और प्यार के बीच हमेशा ही छत्तीस का आंकड़ा रहता है । कभी भी दोनों दुरुस्त नहीं बैठते ।

जब इंसान के पास सही बजट होता है तब प्यार नहीं होता और जब प्यार होता है तब बजट नहीं होता लिहाजा आदमी सपने ही देखता रह जाता है और उसकी हालत शेख चिल्ली जैसी हो जाती है सारी जिंदगी वो अनुमान ही लगाता रह जाता है कि कल जब ऐसा होगा तब वह वैसा करेगा और इन्हीं अनुमानों के बीच आदमी की बारात निकल जाती है ब्याह हो जाता है और बच्चे जन्म ले लेते हैं। मुसीबत ये है कि बजट और प्यार के बीच अनुपात तब भी ठीक नहीं बैठता। मगर जो भी हो हमारे देश में एक बात की तो बड़ी ही सुबिधा है बजट चाहें हो या न हो मगर शादी सबकी हो जाती है इसका अर्थ ये भी निकलता है कि रोटी चाहें ज़रूरी हो या न हो मगर ज़िन्दगी में प्यार भरपूर होना चाहिए। आदमी रोटी के बिना जिंदा रह सकता है मगर प्यार के बिना नहीं रह सकता । आदमी नौकरी भले न तलाश कर पाए मगर वो कहीं न कहीं प्यार तो तलाश कर ही लेता है , यहाँ तक कि घरवाली में न सही तो फिर बाहर वाली में ही सही ।

क्या ही अच्छी बात है कि हमारे यहाँ दीवाली मनाई जाती है, रंगों का पर्व होली मनायी जाती है और प्यार का त्योहार वैलेंटाइन डे भी बड़ी धूम -धाम से मनाया जाता है। दीवाली पर रोशनी बिकती है,होली पर रंग बिकते हैं और वैलेंटाइन डे पर दिल बिकते हैं। हमारे देश में सभी कुछ बिकाऊ है बस खरीदने की ताकत होनी चाहिए फिर सभी कुछ आपकी मुट्ठी में होगा।

हमारे देश में होली दीवाली के अलावा कोई तो ऐसा त्योहार है जिस पर पूड़ी -कचौड़ी, पुए आदि नहीं बनते बल्कि चॉकलेट बांटी जाती है अतः ये बजट में भी लगभग सही ही पड़ता है। प्यार सस्ते बजट का महंगा शौक है इसलिए हर एक की मुट्ठी में नहीं आता। अगर आ गया तो टिक नहीं पाता और अगर टिक गया तो फिर निभ नहीं पाता। ऐसे में वैलेंटाइन डे टूटे हुए दिलों की आखिरी उम्मीद है। सस्ता,सुलभ और आसान! आदमी को इससे ज्यादा भला और क्या चाहिए? कोई भी चीज़ टिकाऊ हो न हो, मगर सुलभ और सुंदर होनी चाहिए।

जैसे पहले के समय मे टिड्डियों के झुंड अचानक से आकर लहलहाती फसलों पर धावा बोल दिया करते थे और पूरी फसल चट कर जाते थे लगभग वही हाल फरवरी के महीने में दिलफेंक प्रेमियों का होता है वे कहाँ से निकल के किस पर धावा बोल देंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए सावधान ! उस पर ये हर साल का शारदीय बजट प्रेमियों के दिल पर बर्फ की तरह गिर पड़ता है जो भावनाएं प्यार की गर्मी पाकर उबाल मारती हुई जान पड़ती हैं वे बजट की शीतलहर के प्रकोप को सहन न कर पाने की वजह से मुरझा जाती हैं। प्रेमियों के चेहरे बिल्कुल इस तरह से पीले पड़ जाते हैं मानों की भरे वसंत पर पतझड़ छा गया हो। मगर इसी बीच वैलेंटाइन डे की आहट से दिल की ठंडी पड़ी ज़मीन पर अरमानों की कोयल इस तरह कुहूकने लगती है मानों की वसंत आ गया हो। आदमी फिर बजट और प्यार के बीच संतुलन बनाने में लग जाता है मगर दुनिया जानती है न तो कभी प्यार संतुलित रहा है और न ही बजट दोनों का ही प्याले से छलक पड़ना मानों कि लाजिमी ही है जिस तरह से प्यार दिलासा देता है कि वह आपका ही होकर रहेगा उसी तरह बजट भी दिलासा देता है कि वह आपका ही होकर रहेगा मगर दोनों ही हिरन की तरह कब कुलाँचें भरने लगेंगे ये कुछ कहा नहीं जा सकता।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए उमेश त्रिवेदी द्वारा अग्निबाण पब्लिकेशन, 121, देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर, म.प्र. से मुद्रित एवं 662, साई कृपा कॉलोनी, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
स्थानीय संपादक
हेमंत पाल
प्रबंध संपादक
रमेश रंजन त्रिपाठी
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2015/ 66040,
Mobile No.: 09893032101
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

कुछ भी हो जागने का नहीं

व्यंग्य

जवाहर चौधरी
लेखक व्यंग्यकार हैं।

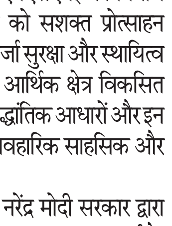

नाम, उम्र, शिक्षा, जाति वगैरह लिखने के बाद जनगणना अधिकारी ने पूछा-' आप सोये हुए हैं या जागे हुए हैं ?'

'जी !! अभी तो जागा हुआ हूँ । मैं रात में ही सोता हूँ ।' भाऊ के कहा ।

'रात से आपका क्या मतलब है ?'

'रात यानी रात ! रोज होती है । आप भी तो जानते होंगे कि रात क्या है !'

'देखिए हम सरकारी नौकर हैं और इस समय ड्यूटी पर हैं । हम जानते हैं लेकिन नहीं जानते हैं, हम सोचते हैं लेकिन नहीं सोचते हैं, हम मानते हैं लेकिन नहीं मानते हैं, हम दो पाए हैं लेकिन नहीं भी हैं । आपको ही बताना पड़ेगा कि रात क्या है ?'

'जब चारों ओर अंधकार हो, चूल्हे ठंडे और रसोईघर बंद हो, नौजवान नशे में लुढ़के पड़े हों, जब मोबाइल पर 'बच्चे चार अच्छे' के मैसेज आ रहे हों, जब सारा देश सो रहा हो, सिर्फ सरकार और उसकी मंडली जाग रही हो । तो समझिए कि रात है ।'

'क्या ये इसी देश की रात है?'

'जी आपने अभी कहा ना कि आप जानते हैं लेकिन नहीं जानते हैं ।'

'ओके... ! तो आप रात में सो जाते है? क्या आपके घर में सब सो जाते हैं ?'

'हाँ, इधर तो पूरा मोहल्ला सो जाता है। हम भी सो जाते हैं । जब सब सो रहे हों तो अकेले जागने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है।' भाऊ ने कारण सहित जवाब दिया।

'इसका मतलब सबको नींद आ जाती है। सब सुखी हैं । यह नया स्टार्ट-अप है ।'

'सुख-वुख कुछ नहीं साहब, आँखें बंद करके पड़े रहो तो नींद भी आ ही जाती है ।'

'आपको जान कर खुशी होगी कि जल्द ही निंद्रा सुख-टेक्स लगाया जा सकता है ।'

'निंद्रा सुख-टेक्स क्यों? '

'सरकार का काम है टेक्स लगाना।

आपको लाडले-भाऊ टेक्स-पेयर भी बनाना है ।' 'ओह! मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सो रहा हूँ या जाग रहा हूँ !!'

'जब समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है आप सो रहे हैं । आँख खुली होने से केवल आँख खुली होती है। नवीन देशभक्त आँख खुली रखते है लेकिन असल में सोये हुए होते हैं । आप भी देशभक्त हो।'

'अगर मैं इस बात से इंकार करूँ तो ?' भाऊ डर सा गया ।

'अपनी रिस्क पर आप कुछ भी कर सकते हैं । (ईश्वर आपकी रक्षा करे)।'

सच बात यह है कि भाऊ ने लगातार इतना 'जागो जागो' सुन लिया कि अब जागना जोखिम का हो गया है । उसे जगाने वालों का षड्यंत्र समझ में आ गया है । वो जागने को कहते हैं लेकिन चाहते हैं कि लोग आँखे बंद रखें। अधिकारी ठीक कह रहे हैं । हर बात में रिस्क दिखाई देती है। बल्कि रिस्क ही रिस्क दिखाई देती है। दस ग्राम सोना दो लाख तक पहुँच गया, भाऊ जरा सा चौंका और फिर सो गया । सोने के भाव से उसे क्या मतलब! शंकराचार्य ने आवाज लगाई 'आओ बचाओ'। उसने एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया । शंकराचार्य से उसे क्या लेना देना! बनारस के घाट पर तोड़फोड़ हुई वह नहीं जागा । अपुन को क्या! चित्रकूट के मंदिर पर बुलडोजरों ने सेवा की, वह सोया रहा। अब भगवान ही निबटें। मलमूत्र वाला पानी पी कर तमाम लोग मर गए, भाऊ आँखें बंद किये लेटा रहा। सोचा 'आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर' ...। मानो उसने तय कर लिया है कि कुछ भी हो जाए वह नहीं जागेगा।

एपस्टीन फाइल्स

डॉ. सत्यवान सौरभ
लेखक स्तंभकार हैं।

लोकतंत्र का आईना या सत्ता का कवर-अप?

नवंबर 2025 में अमेरिकी कांग्रेस ने एपस्टीन फाइल्स पारदर्शिता अधिनियम पारित किया। इसके तहत जनवरी 2026 तक 33 लाख से अधिक पृष्ठ सार्वजनिक किए जा चुके हैं। इनमें ई-मेल संवाद, उड़ान लॉग, संपर्क सूचियाँ, वित्तीय लेन-देन और जांच एजेंसियों की आंतरिक रिपोर्टें शामिल हैं। इन दस्तावेज़ों में अमेरिका ही नहीं, बल्कि कई देशों के राजनीतिक, कारोबारी और कूटनीतिक हलकों के संदर्भ सामने आए हैं। भारत का नाम भी इन्हीं संदर्भों में उभर कर आया है, जिसने इस बहस को और तीखा बना दिया है। जेफरी एपस्टीन का नेटवर्क कोई साधारण अपराध नहीं था। न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा और कैरिबियन द्वीपों तक फैले इस जाल में दुनिया के कई प्रभावशाली लोगों के शामिल होने के आरोप रहे हैं। 2019 में अमेरिकी जेल में उसकी रहस्यमय मौत के बाद वर्षों तक फाइल्स सील रहीं। लेकिन पीड़ितों के दबाव, मीडिया की पड़ताल और न्यायिक हस्तक्षेप ने सरकार को इन्हें सार्वजनिक करने के लिए बाध्य किया। जुलाई 2025 में जारी पहले बैच में गिस्लेन मैक्सवेल के मुकदमे से जुड़े कई नाम सामने आए। ट्रंप, क्लिंटन और ब्रिटिश शाही परिवार से जुड़े संदर्भ पहले ही चर्चा में थे, लेकिन नए दस्तावेज़ों ने बहस को वैश्विक स्तर पर फैला दिया।

अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा सार्वजनिक की जा रही एपस्टीन फाइल्स केवल एक आपराधिक कांड का खुलासा नहीं हैं, बल्कि वे आधुनिक लोकतंत्रों की पारदर्शिता, जवाबदेही और सत्ता-संरचना पर गंभीर प्रश्न खड़े करती हैं। जेफरी एपस्टीन–एक ऐसा नाम, जो वित्तीय वैभव, राजनीतिक पहुँच और यौन शोषण के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का पर्याय बन चुका है–की मृत्यु के छह वर्ष बाद उसके दस्तावेज़ सामने आ रहे हैं। इन फाइल्स का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि ये दिखाती है कि किस प्रकार सत्ता, पूंजी और गोपनीय नेटवर्क लोकतांत्रिक संस्थाओं को भीतर से प्रभावित करते हैं।

नवंबर 2025 में अमेरिकी कांग्रेस ने एपस्टीन फाइल्स पारदर्शिता अधिनियम पारित किया। इसके तहत जनवरी 2026 तक 33 लाख से अधिक पृष्ठ सार्वजनिक किए जा चुके हैं। इनमें ई-मेल संवाद, उड़ान लॉग, संपर्क सूचियाँ, वित्तीय लेन-देन और जांच एजेंसियों की आंतरिक रिपोर्टें शामिल हैं। इन दस्तावेज़ों में अमेरिका ही नहीं, बल्कि कई देशों के राजनीतिक, कारोबारी और कूटनीतिक हलकों के संदर्भ सामने आए हैं। भारत का नाम भी इन्हीं संदर्भों में उभर कर आया है, जिसने इस बहस को और तीखा बना दिया है।

जेफरी एपस्टीन का नेटवर्क कोई साधारण अपराध नहीं था। न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा और कैरिबियन द्वीपों तक फैले इस जाल में दुनिया के कई प्रभावशाली लोगों के शामिल होने के आरोप रहे हैं। 2019 में अमेरिकी जेल में उसकी रहस्यमय मौत के बाद वर्षों तक फाइल्स सील रहीं। लेकिन पीड़ितों के दबाव, मीडिया की पड़ताल और न्यायिक हस्तक्षेप ने सरकार को इन्हें सार्वजनिक करने के लिए बाध्य किया। जुलाई 2025 में जारी पहले बैच में गिस्लेन मैक्सवेल के मुकदमे से जुड़े कई नाम सामने आए। ट्रंप, क्लिंटन और ब्रिटिश शाही परिवार से जुड़े संदर्भ पहले ही चर्चा में थे, लेकिन नए दस्तावेज़ों ने बहस को वैश्विक स्तर पर फैला दिया।

भारत से जुड़े आरोपों और दावों ने स्वाभाविक रूप से राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। फाइल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अप्रत्यक्ष उल्लेख, उद्योगपति अनिल अंबानी से संबंधित कुछ ई-मेल और पूर्व राजनयिक हर्ष पुरी के नाम सामने आने का दावा किया गया है। 2017 के कुछ ई-मेल संवादों में यह संकेत दिया गया है कि अमेरिकी राजनयिक नियुक्तियों, अंतरराष्ट्रीय बैठकों और प्रभाव-निर्माण में एपस्टीन से सलाह ली गई। एक ई-मेल में एपस्टीन द्वारा यह दावा किया गया है कि उसने भारत-इज़रायल कूटनीतिक संवाद के दौरान अमेरिकी नेतृत्व को प्रभावित करने में भूमिका निभाई।

भारत सरकार ने इन दावों को पूरी तरह निराधार और कचरा करार दिया है। सरकार का यह कहना स्वाभाविक है, क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसे आरोप गंभीर होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि यदि आरोप असत्य हैं, तो स्वतंत्र और पारदर्शी जांच से परहेज़ क्यों? लोकतंत्र में सरकार की विश्वसनीयता केवल खंडन से नहीं, बल्कि जांच और जवाबदेही से स्थापित होती है।

यह विवाद केवल भारत तक सीमित नहीं है। अमेरिका में भी ट्रंप प्रशासन पर आरोप लगे हैं कि उसने दस्तावेज़ों को जारी करने में अनावश्यक देरी की और कुछ हिस्सों को छिपाने की कोशिश की। रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी और डेमोक्रेट नेताओं ने न्यायिक निगरानी की मांग की है। इससे स्पष्ट होता है कि दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र भी सत्ता और पारदर्शिता के टकराव से अछूता नहीं है।

भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में यह बहस और गहरी हो जाती है। हमारा राजनीतिक तंत्र पहले ही प्रॉक्सी नेतृत्व, कॉरपोरेट प्रभाव और अपारदर्शी निर्णय-प्रक्रियाओं की आलोचना झेल रहा है। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को पचास प्रतिशत आरक्षण मिला है, लेकिन कई जगह वास्तविक सत्ता आज भी प्रॉक्सी पुरुषों के हाथों में है। यह केवल स्थानीय स्तर की समस्या नहीं, बल्कि सत्ता-संरचना की व्यापक प्रवृत्ति को दर्शाती है–जहां औपचारिक लोकतांत्रिक ढाँचे के पीछे अनौपचारिक नेटवर्क निर्णय लेते हैं।

एपस्टीन फाइल्स इसी प्रवृत्ति का वैश्विक रूप हैं। सतह पर लोकतंत्र चमकता है, लेकिन भीतर संपर्क, धन और गोपनीयता का खेल चलता है। भारत में कोहिनूर विवाद, राफेल सौदा या चुनावी बॉन्ड जैसी व्यवस्थाओं पर उठे सवाल इसी कारण विश्वास के संकट को जन्म देते हैं। जब पारदर्शिता अधूरी होती है, तो अफवाहें और संदेह स्वाभाविक रूप से पनपते हैं। वैश्विक स्तर पर ये फाइल्स पूंजीवाद और सत्ता के गठजोड़ को उजागर करती हैं। एक ऐसा अभिजात्य वर्ग, जहां कानून अक्सर कमजोर पड़ जाता है और प्रभावशाली लोग जवाबदेही से बच निकलते हैं। भारत जैसे उभरते लोकतंत्र के लिए यह चेतावनी है। हमारी अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण के दौर में तेज़ी से आगे बढ़ रही है–विदेशी निवेश, स्टार्ट-अप संस्कृति और अंतरराष्ट्रीय साझेदारियाँ बढ़ रही हैं। लेकिन क्या हमारी संस्थाएँ इतने मज़बूत हैं कि वे छिपे हुए प्रभाव-जालों का सामना कर सकें?

राजनीतिक दृष्टि से भी यह मुद्दा महत्वपूर्ण है। 2029 के आम चुनावों से पहले ऐसे खुलासे राजनीतिक विमर्श को प्रभावित कर सकते हैं। विपक्ष का कर्तव्य है कि वह सवाल उठाए, लेकिन उससे भी अधिक ज़रूरी है कि संसद में गंभीर और तथ्यात्मक बहस हो। सर्वोच्च न्यायालय को, आवश्यकता पड़ने पर, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए ताकि संस्थागत विश्वास बना रहे।

समाधान के रास्ते स्पष्ट हैं। पहला, भारत से जुड़े सभी संदर्भों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच–राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त। दूसरा, संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों और वरिष्ठ अधिकारियों के विदेशी संपर्कों का नियमित सार्वजनिक प्रकटीकरण। तीसरा, सूचना के अधिकार को और मज़बूत करना तथा राजनीतिक फंडिंग में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करना। अंतरराष्ट्रीय मंचों, जैसे जी-20, पर साइबर और वित्तीय पारदर्शिता को एजेंडा बनाना भी ज़रूरी है।

एपस्टीन फाइल्स केवल एक व्यक्ति या कांड की कहानी नहीं हैं। वे यह बताती हैं कि लोकतंत्र की असली परीक्षा सत्ता से सवाल पूछने में है। यदि हम सवालों को दबा देंगे, तो सत्ता का आईना धुंधला होता जाएगा। ग्रामीण भारत की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से लेकर संसद और वैश्विक मंचों तक–हर स्तर पर जवाबदेही लोकतंत्र की प्राणवायु है।

समय रहते सुधार किए गए, तो लोकतंत्र मजबूत होगा। अन्यथा रहस्य, नेटवर्क और अपारदर्शिता लोकतांत्रिक संस्थाओं को भीतर से खोखला करती रहेंगी।

सत्ता जवाबदेह हो–यही गणराज्य का मूलमंत्र है।

खेल

लोकेंद्र नामजोशी

शिक्षा में शतरंज की पहल भारत के लिए सुनहरा अवसर

भारतीय संदर्भ में यह पहल विशेष महत्व रखती है। शतरंज में निरंतर उभरते भारत जैसे देश के लिए शिक्षा व्यवस्था में शतरंज को शामिल करने की यह अवधारणा एक बहुउपयोगी अवसर है। किंतु इस अवसर का हम कितना लाभ उठा पाएंगे, यह हमारी नीतियों और संस्थागत इच्छाशक्ति पर निर्भर करता है। वर्तमान में हमारे देश के अनेक शैक्षणिक संस्थान और खेल संगठन शतरंज को अब भी सीमित वर्ग का खेल मानते हैं। यह धारणा बनी हुई है कि औसत बच्चे के लिए शतरंज में भविष्य बनाना संभव नहीं है।

शतरंज के खेल में तेज़ी से उभरते भारत के लिए यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि विश्व शतरंज महासंघ ने वर्ष 2026 को 'शिक्षा में शतरंज का वर्ष' घोषित किया है। इस घोषणा का उद्देश्य शतरंज को केवल एक खेल के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रभावी शैक्षिक उपकरण के रूप में वैश्विक मान्यता दिलाना है, ताकि विश्व के सभी स्कूली बच्चों तक इस बौद्धिक खेल की व्यापक पहुँच सुनिश्चित की जा सके। यदि भारत में शिक्षा में शतरंज की इस पहल को समग्र रूप से लागू किया जाता है, तो भारत में शतरंज के भविष्य के लिए यह एक बहुत ही सुनहरा अवसर साबित हो सकता है।

भारतीय संदर्भ में यह पहल विशेष महत्व रखती है। शतरंज में निरंतर उभरते भारत जैसे देश के लिए शिक्षा व्यवस्था में शतरंज को शामिल करने की यह अवधारणा एक बहुउपयोगी अवसर है। किंतु इस अवसर का हम कितना लाभ उठा पाएंगे, यह हमारी नीतियों और संस्थागत इच्छाशक्ति पर निर्भर करता है। वर्तमान में हमारे देश के अनेक शैक्षणिक संस्थान और खेल संगठन शतरंज को अब भी सीमित वर्ग का खेल मानते हैं। यह धारणा बनी हुई है कि औसत बच्चे के लिए शतरंज में भविष्य बनाना संभव नहीं है। इसी सोच के कारण देश के अधिकांश हिस्सों में शतरंज को जन-जन तक पहुँचाने के लिए कोई ठोस पहल नहीं की गई। परिणामस्वरूप शतरंज आज भी भारत के लोकप्रिय खेलों में स्थान नहीं बना पाया है, जबकि वास्तविकता यह है कि शतरंज उन गिने-चुने खेलों में शामिल है, जिसे न्यूनतम संसाधनों और केवल दो खिलाड़ियों के साथ खेला जा सकता है। स्थानीय खेल संगठनों की उदासीनता के कारण यह खेल आज भी औसत बच्चों तक नहीं पहुँच सका है। ऐसी परिस्थितियाँ केवल भारत तक सीमित नहीं हैं, बल्कि विश्व के अनेक देशों में देखने को मिलती हैं। इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए FIDE ने 'शिक्षा में शतरंज' को वैश्विक स्तर पर लागू करने का निर्णय लिया है।

इस निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए विश्व शतरंज महासंघ वर्ष 2026 में विश्वभर में शतरंज को बढ़ावा देने हेतु विविध कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। इसके अंतर्गत विभिन्न देशों की सरकारों, नीति-निर्माताओं और खेल संगठनों के सहयोग से 'वर्ल्ड स्कूल्स टीम चैंपियनशिप लीग

2026' जैसे आयोजन किए जाएंगे। इन प्रतियोगिताओं का उद्देश्य बच्चों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा का अनुभव प्रदान करना है। साथ ही FIDE एक वैश्विक सर्वेक्षण और डेटा-आधारित नीति पर भी कार्य कर रहा है, जिसके माध्यम से यह समझा जा सकेगा कि विभिन्न देशों में शतरंज-शिक्षा कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त विश्व शतरंज महासंघ, इंटरनेशनल स्कूल चेस फेडरेशन सहित अन्य सहयोगी संगठनों के साथ मिलकर प्रशिक्षण मॉड्यूल, प्रतियोगिताएँ और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है, ताकि राष्ट्रीय शतरंज संघ, शैक्षणिक संस्थान, मंत्रालय और गैर-सरकारी संगठन वैश्विक स्तर पर आपस में जुड़ सकें और बच्चों को बेहतर अवसर प्रदान किए जा सकें।

यदि भारत के शतरंज इतिहास पर दृष्टि डालें, तो एक समय ऐसा भी था जब इस खेल की उत्पत्ति का दावा करने वाला हमारा देश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कहीं ठहर नहीं पाता था। तब अमेरिका, रूस, नॉर्वे और यूरोपीय देशों का दबदबा था। भारतीय दर्शक केवल बॉबी फिशर, गैरी कैस्परोव, अनातोली कारपोव और मिखाइल बोट्विनिक जैसे दिग्गजों के नाम जानते थे। वर्ष 2000 में विश्वनाथन आनंद के विश्व चैम्पियन बनने के बाद स्थिति में बदलाव आया, लेकिन लगभग एक दशक तक वे अकेले ही भारत का प्रतिनिधित्व करते रहे। वर्ष 2011 के बाद परिदृश्य बदला और भारत से नई पीढ़ी के खिलाड़ी उभरकर सामने आए। पिछले कुछ वर्षों में डी. गुकेश, रमेशबाबू प्रज्ञानानंद, अर्जुन एरिगैसी और महिला वर्ग में कोनेरू हम्पी, हरिका द्रोणावल्ली, वैशाली रमेशबाबू, दिव्या देशमुख और तानिया सचदेव जैसी प्रतिभाओं ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं। इसके बावजूद भारत के पास आज भी गिने-चुने ग्रैंडमास्टर ही हैं, जिनके सहारे हम विश्व शतरंज में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास कर रहे हैं। यह स्पष्ट संकेत है कि इस स्थिति को बदलने की तत्काल आवश्यकता है।

यदि भारत के नीति-निर्माता, खेल संगठन और शैक्षणिक संस्थान FIDE की 'शिक्षा में शतरंज' की अवधारणा को गंभीरता और ईमानदारी से लागू करें, तो भारत के लिए निश्चित रूप से एक सुनहरा अवसर है। इससे न केवल शतरंज का आधार व्यापक होगा, बल्कि भविष्य में अनेक नए भारतीय ग्रैंडमास्टर तैयार होने का मार्ग भी प्रशस्त होगा।

मुद्दा

भारती पंडित
लेखक सामाजिक कार्यकर्ता हैं।

जरूरत है कि शिक्षा को सामूहिक ज़िम्मेदारी समझा जाए

एक और प्राथमिक विद्यालय है जो सघन बस्ती में स्थित है। इसी परिसर में एक आँगनवाड़ी भी है। इस बस्ती में स्कूल परिसर ही एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ बस्ती के लोग आवारागर्दी करने के लिए इकट्ठे हो सकते हैं इसके चलते स्कूल की चारदीवारी बार-बार यहाँ-वहाँ से तोड़ दी जाती है। शाम होते ही स्कूल के परिसर में लोगों का जमावड़ा हो जाता है, शराब पी जाती है और बोतलें तोड़कर फेंक दी जाती हैं जिसके काँच यत्र-तत्र बिखरे रहते हैं और बच्चों के पाँव में लग जाते हैं। इसके अलावा बस्ती के लोग अपने अवैध वाहन खड़े करने के लिए इस परिसर का धड़ल्ले से उपायोग करते हैं। स्कूल द्वारा न जाने कितनी बार शिकायत की गई है पर कोई निराकरण हो पाया है। 'हम लोग शिकायत कर-करके थक गए हैं, इसके अलावा ये लोग हमें ही धमकाते हैं कि कोई कार्यवाही हुई तो देख लीजिए...हम बस यही कर सकते हैं कि अपने बच्चों को सुरक्षित रखें।' यहाँ कार्यरत शिक्षिका ने बताया।

राजधानी के दूरस्थ इलाके में एक बस्ती में बना सरकारी स्कूल, स्कूल में जाने के लिए पक्की सड़क छोड़कर पतली गली सी दिखाई देने वाली मिट्टी भरी सड़क पर उतरना पड़ता है, दिखने को भली ही यह सड़क दिखाई देती हो, मगर घरों से निकला गंदा पानी पूरी सड़क पर फैलकर कीचड़ बनाता रहता है, जिस पर दो पहिया वाहनों का फिसलना तय है। किसी संभावित दुर्घटना से बचने के लिए इस स्कूल में पढ़ाने वाली दोनों शिक्षिकाएँ अपने वाहन पक्की सड़क के किनारे लगे एक पेड़ के नीचे लगाकर पैदल स्कूल तक जाती हैं। स्कूल के रास्ते में और स्कूल के मैदान के पास जहाँ थोड़ी पक्की जगह है, बस्ती के पुरुष हर दिन आधे-अधूरे कपड़ों में बीड़ी सुलगाए या कभी गिलास हाथ में लिए ताश खेलते नज़र आते हैं, उनकी नज़रों से, उनकी गाली-गलौज भरी भाषा से खुद को और स्कूल की लड़कियों को बचाने की ज़िम्मेदारी लिए ये शिक्षिकाएँ यहाँ पूरी निष्ठा से पढ़ाने आती हैं।

'हम स्कूल तक सकुशल पहुँच जाएँ यही हमारे लिए हर दिन की चुनौती है...फिर दूसरी चुनौती यह कि हम घर के काम में जोत दी गईं लड़कियों को किसी तरह से दो-तीन घंटे ही सही, स्कूल में लेकर आ सकें। बस यही प्रयास करते हैं।' शिक्षिका ने बताया।

एक और प्राथमिक विद्यालय है जो सघन बस्ती में स्थित है। इसी परिसर में एक आँगनवाड़ी भी है। इस बस्ती में स्कूल परिसर ही एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ बस्ती के लोग आवारागर्दी करने के लिए इकट्ठे हो सकते हैं इसके चलते स्कूल की चारदीवारी बार-बार यहाँ-वहाँ से तोड़ दी जाती है। शाम होते ही स्कूल के परिसर में लोगों का जमावड़ा हो जाता है, शराब पी जाती है और बोतलें तोड़कर फेंक दी जाती हैं जिसके काँच यत्र-तत्र बिखरे रहते हैं और बच्चों के पाँव में लग जाते हैं। इसके अलावा बस्ती के लोग अपने अवैध वाहन खड़े करने के लिए इस परिसर का धड़ल्ले से उपायोग करते हैं। स्कूल द्वारा न जाने कितनी बार शिकायत की गई है पर कोई निराकरण हो पाया है।

'हम लोग शिकायत कर-करके थक गए हैं, इसके अलावा ये लोग हमें ही धमकाते हैं कि कोई कार्यवाही हुई तो देख लीजिए...हम बस यही कर सकते हैं कि अपने बच्चों को सुरक्षित रखें।' यहाँ कार्यरत शिक्षिका ने बताया।

मज़े की बात यह है कि इन दोनों बस्तियों के अधिकतर बच्चे इन्हीं स्कूलों में पढ़ते हैं पर समुदाय का सहयोग शून्य है।

'मेरे स्कूल में आने वाले बच्चे सिग्नल और मंदिरों के सामने भीख माँगते हैं, उनके माँ-बाप उन्हें सुबह से भीख माँगने ले जाते हैं। स्कूल आते समय कई बार मुझे अपने स्कूल की लड़कियाँ सिग्नल पर भीख माँगती दिखाई देती हैं तो मैं उन्हें पकड़कर ऑटो में बिठाकर स्कूल ले आती हूँ। सबसे बड़ा संघर्ष तो उन्हें स्कूल तक लेकर आने का ही है। पढ़ाई तो दूर की बात है।' शिक्षिका की आवाज़ में चिंता और लाचारी दोनों स्पष्ट झलक रही थी।

'इस बस्ती में लड़कियों को शादी के नाम पर रुपए

लेकर बेच देते हैं, लड़कियाँ शादी नहीं करना चाहतीं, पढ़ना चाहती हैं, पर उनके साथ उनके माता-पिता ही जबर्दस्ती करते हैं। जिन लड़कियों ने इस बारे में हमें बताया, उनको लेकर हम पुलिस के पास गए और उनकी शादियाँ रुकवाईं। बस्ती के लोग हमसे नाराज़ हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ का स्कूल बंद हो जाए। पर हम जब तक यहाँ हैं, इन लड़कियों की पढ़ाई रुकने नहीं देंगे।' तीनों शिक्षिकाओं ने मजबूती से कहा।

'इस बस्ती की लड़कियाँ पढ़ने आती ही नहीं थी, बात करने पर पता चला कि उन्हें घर में खाना बनाने के साथ-साथ छोटे भाई-बहनों की देखभाल करनी पड़ती है ताकि उनके माँ-बाप काम पर जा सकें। हमने आपस में बात करके उनके छोटे भाई-बहनों को भी स्कूल में बैठने की सुविधा दे दी, अब ये लड़कियाँ कम से कम स्कूल तो आ पाती हैं।' एक और स्कूल की शिक्षिका ने उल्लेख किया।

ऐसे कुछ एक नहीं, अनेक किस्से हैं, कितने ही जटिल मोर्चे हैं जिन पर बहुतेरे सरकारी शिक्षकों को कमर कसकर खड़ा होना पड़ता है। बच्चों को स्कूल तक लाना तो कवायद है ही, इसके बाद कुछ स्कूलों में कमरे नहीं हैं, कुछ में छत गिरने की कगार पर है, कुछ में शिक्षक नहीं हैं, पाँच कक्षाएँ एक साथ पढ़ाना मजबूरी है।

इसके बाद चुनावी सर्वे, जनगणना और अन्य विभागीय जानकारियाँ देने जैसे कितने ही काम हैं जिनके चलते शिक्षक इतनी विषम परिस्थितियों के बावजूद पढ़ाना चाहें भी तो न पढ़ा सकें।

क्या इस सबको देखकर ऐसा लगता भी है कि शिक्षा वास्तव में समुदाय और शासन के लिए महत्वपूर्ण उद्यम है? समुदाय यदि थोड़ी भी ज़िम्मेदारी समझें तो उनकी बस्ती के स्कूल बेहतर स्थिति में होंगे और बच्चे बेहतर तरीके से, अच्छे वातावरण में पढ़ सकेंगे।

कुछ जुझारू शिक्षकों ने समुदाय के युवाओं और किशोरों को लेकर समुदाय में जागृति फैलाने का काम किया है और स्कूल परिसर को स्वच्छ और सुरक्षित बनाया है पर इनकी संख्या बहुत कम है। यहाँ मेरा मत यह भी है कि शिक्षकों का मूल काम बच्चों को पढ़ाना है, इस तरह के रोज़मर्रा के संघर्षों को उनकी दिनचर्या का हिस्सा नहीं होना चाहिए। यदि स्कूल पहुँचना, बच्चों की सुरक्षा आदि ही यदि प्रधान कार्य बन जाए, तो कक्षा शिक्षण निश्चित ही गौण होता जाएगा।

इसके लिए जरूरी यह है कि शिक्षा को सामूहिक ज़िम्मेदारी समझा जाए, जिसमें शिक्षक, समाज और सरकार सभी का सहयोग रहे, सभी की जवाबदेही तय हो। यदि सरकार के लिए वास्तव में शिक्षा महत्वपूर्ण होगी तो वे शिक्षकों को अन्य कार्यों में व्यस्त रखने की बजाय कक्षा में पढ़ाने का समय देंगे। जब शिक्षकों की जवाबदेही तय होगी तो वे भी शिक्षण कार्य को गंभीरता से लेंगे और यदि समुदाय जागरूक होगा तो वह स्कूल को बिगाड़ने में नहीं, सँवारने में मदद करेगा।

पुण्यतिथि विशेष

रमेश रंजन त्रिपाठी

स्वाभिमानी लता मंगेशकर

सन् 1952 की बात है। ओ. पी. नैय्यर अपनी पहली फिल्म 'आसमान' के लिए संगीत तैयार कर रहे थे। नैय्यर इस फिल्म में लता मंगेशकर की आवाज़ में ऐसा गाना रिकॉर्ड करना चाहते थे जिसे साइड हीरोइन पर फ़िल्माया जाना था। उस समय तक लता जी पार्श्व गायिका के रूप में स्थापित हो चुकी थीं। यह गाना रिकॉर्ड नहीं हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि लता जी रिकॉर्डिंग पर नहीं पहुँचीं। इसके बाद लता जी और नैय्यर ने कभी साथ में काम नहीं किया। इसे लेकर तरह-तरह की बातें कही सुनी जाती हैं। अलग-अलग काम करते हुए आने वाले समय में, लता जी और नैय्यर, दोनों शिखर पर पहुँचे। यह सवाल बहुत दिलचस्प हो सकता है कि लता जी और नैय्यर साहब साथ में काम करते तो?

लता जी ने ओ. पी. नैय्यर के संगीत निर्देशन में कभी नहीं गाया। लेकिन भिन्न-भिन्न कारणों से कुछ और लोगों से, अल्प समय के लिए ही सही, उनकी अनबन की खबरें आती रहती थीं। पचास के दशक के अंत में संगीतकार सचिन देव बर्मन ने कभी यह कह दिया था कि लता मंगेशकर की सफलता का श्रेय उन्हें जाता है। इसके बाद कुछ साल दोनों के बीच मनमुटाव रहा, जो साठ के दशक की शुरुआत में राहुल देव बर्मन के कारण समाप्त हुआ। पंचम जब 'छोटे नवाब' (1961) में स्वतंत्र रूप से संगीत दे रहे थे तो सचिन दा' ने स्वयं लता जी से अपने बेटे के लिए पहला गाना गाने का अनुरोध किया था। बस, दोनों महान हस्तियों के बीच फिर से संबंध मधुर हो गए।

गायकों को रॉयल्टी मिलने के मुद्दे पर वैचारिक मतभेद के चलते मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के बीच अनबन हो गई। दोनों ने 1963 से 1967, चार साल तक साथ में कोई युगल गीत नहीं गाया। इसका कुछ लाभ आशा भोंसले, सुमन कल्याणपुर, महेंद्र कपूर जैसे गायकों को मिला। दिग्गज संगीतकार एस. डी. बर्मन और जयकिशन के प्रयासों से यह गतिरोध समाप्त हुआ और 'ज्वैल थीफ' में 'दिल पुकारे, आ रे आ रे आ रे' जैसे गीत से मधुरता का सिलसिला फिर चल पड़ा।

एक बार किसी ने प्रख्यात गीतकार साहिर लुधियानवी से कह दिया कि वे खुशकिस्मत हैं कि लता मंगेशकर उनके गीत गाती हैं। इस बात का बुरा मानना साहिर जैसी शख्सियत के लिए अस्वाभाविक नहीं था। साहिर ने घोषणा कर दी कि जिस फिल्म में लता जी पार्श्व गायन करेंगी उसमें वे गीत नहीं लिखेंगे। कुछ सालों तक ऐसा हुआ भी। इस अनबन को यश चोपड़ा जैसे फ़िल्मकारों ने दूर कराया और 'कभी-कभी' के सदाबहार गीत बन सके।

सी. रामचंद्र जैसे बड़े संगीतकार ने 'अनारकली', 'आज़ाद', 'अलबेला' जैसी अपनी अनेक फ़िल्मों के गानों से लता जी को चोटी तक पहुंचने में अहम योगदान दिया। उन्हीं सी. रामचंद्र से लता जी के तथाकथित अनबन की खबरें भी आई थीं। संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के शंकर द्वारा गायिका शारदा को बढ़ावा देने के बाद लता जी से उनका मनमुटाव हो गया जिसे रफी साहब के साथ लता जी का 'रॉयल्टी विवाद' सुलझाने वाले जयकिशन भी दूर नहीं कर सके। इस बीच सन् 1971 में जयकिशन चल बसे। बहुत बाद में 'संन्यासी' (1975) में लता मंगेशकर ने शंकर के लिए गीत गाए।

लता जी के जीवन की इन घटनाओं के पीछे अथक परिश्रम और ईमानदार सत्प्रयासों से अर्जित किया हुआ स्वाभिमान है। जीते जी किंवदंती बन जाना, अपने लिए किसी परिचय का मोहताज ना रहना ही लता मंगेशकर होना है। मनमुटाव के मुट्ठी भर क़िस्सों की अपेक्षा उनके मधुर रिश्तों के अनेक उदाहरण मौजूद हैं। मदन मोहन, मुकेश, किशोर कुमार, नौशाद की तरह बहुत सी हस्तियों के साथ उनके घनिष्ठ संबंध थे जो ताजिंदगी रहे। भारतीय सिनेमा की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री मधुबाला फिल्म साइन करते समय यह शर्त रखती थीं कि उनके गाने लता जी गाएँगी। ऐसा सम्मान किसी और गायक के नाम दर्ज नहीं है। लता मंगेशकर स्वयं महान गायक के. एल. सहगल की दीवानी थीं। इतनी कि बचपन में कहा करती थीं कि वे सहगल से शादी करेंगी। सहगल के गीत सुनने के लिए उन्होंने रेडियो खरीदा और पहली बार उसे चालू किया तो उसमें सहगल की मौत की खबर सुनाई जा रही थी। वे इतनी दुखी हो गईं कि तत्काल उस रेडियो को वापस कर दिया। सहगल साहब से न मिल पाने का अफसोस उन्हें हमेशा रहा। लता जी का पूरा व्यक्तित्व उनके दृढ़ निश्चयी, सादगीपूर्ण, उज्ज्वल और पावन जीवन का प्रतिबिंब था। इन विशेषताओं के द्योतक थे, श्वेत अथवा क्रीम रंग का परिधान, हीरे के एक-दो आभूषण और मेकअप का मोहताज न रहनेवाले चेहरे पर अनोखी आभायुक्त दिव्य सौम्यता। रेकॉर्डिंग रूम में प्रवेश से पहले चप्पल उतारना, गानों के चयन में सावधानी बरतना, भूलकर भी बेसुरा न गाना, विनम्रता के साथ अपनी अपार सफलता का श्रेय भगवान को देना, उनकी अनेक खूबियों का हिस्सा ही तो थीं। वे हमारे बीच नहीं हैं लेकिन उनका महान व्यक्तित्व और दिव्य स्वर सदैव हमें ईश्वरीय सत्ता का भान कराते रहेंगे।

देव प्राण-प्रतिष्ठा में शंकराचार्य होंगे शामिल

श्रीमद् भागवत पुराण के साथ निकाली कलशयात्रा

सुबह सवेरे, सोहागपुर। समीपवर्ती ग्राम करनपुर में देव प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में आज श्रीमद् भागवत पुराण के साथ भव्य कलशयात्रा निकाली गई। श्रीमद् भागवत पुराण को समाजसेवी हरगोविंद पुरबिया अपने मस्तिष्क के ऊपर रखकर चल रहे थे। इसके साथ ही भारी संख्या में महिलाएं कलश लेकर चल रही थी। इस कलश यात्रा में ग्राम करनपुर के अलावा अन्य नगरों गणमान्य नागरिक भी शामिल थे। उल्लेखनीय है कि देश प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव 05 फरवरी 2026 गुरुवार से दिनांक 11 फरवरी 2026 बुधवार को सम्पन्न

होगा। इस प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव समारोह में जगद्गुरू वंश जी भगवान का पावन महाभिनन्दनोत्सव पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित पश्चिमाम्नाय द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर स्वामी सदानन्द सरस्वती जी महाराज एवं यज्ञाचार्यः-पं. श्री सनत्कुमार जी उपाध्याय शारदापीठ द्वारिका के आचार्यत्व में कथा व्यासः-आचार्य पं. श्री पवन शास्त्री जी (पोसेरा) करेंगे।

11फरवरी तक चलने वाले धार्मिक महोत्सव में देव प्राण प्रतिष्ठा एवं भगवत सत्संग का भव्य आयोजन किया जा रहा है। आयोजक समाजसेवी हरगोविंद पुरबिया ने क्षेत्र के धर्मप्रेमियों से कार्यक्रम में शामिल होकर पुण्यलाभ अर्जित करने का आग्रह किया है। ज्ञातव्य है कि समाजसेवी हरगोविंद पुरबिया ने ग्राम करनपुर में भव्य मंदिर निर्माण कराया है। जिसमें शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी के सानिध्य में देव प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव समारोह संम्पन्न होगा। कार्यक्रम के अंतिम दिवस 11 फरवरी को यहां प्रसादी भंडारे का भी आयोजन किया गया है।

भोपाल में किसानों के काम की खबर

गेहूं बेचने के लिए 7 फरवरी से रजिस्ट्रेशन; सोसायटी में फ्री, साइबर कैफे पर फीस लगेगी

भोपाल (नप्र)। भोपाल में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए 7 फरवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस ऑनलाइन होगी। सहकारी सोसायटी या खुद के मोबाइल से पंजीयन करने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, लेकिन यदि एमपी ऑनलाइन, कियोस्क सेंटर या लोक सेवा केंद्र से रजिस्ट्रेशन कराया जाता है तो उसकी फीस लगेगी।

कहां करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन

एमपी ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्र और प्राइवेट साइबर कैफे पर रजिस्ट्रेशन कराए जा सकते हैं। यहां किसानों को प्रति रजिस्ट्रेशन की फीस 50 रुपए तक चुकानी होगी। सहकारी समितियों, मोबाइल पर पंजीयन एप पर निःशुल्क रजिस्ट्रेशन होंगे। भोपाल में कुल 47 सहकारी समितियों में किसान पंजीयन केंद्र स्थापित किए गए हैं।

क्या-क्या दस्तावेज जरूरी होंगे?

पंजीयन कराते समय किसानों को कुछ दस्तावेज रखने होंगे। जमीन की किताब, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट की पासबुक। बैंक अकाउंट से आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। यह अति महत्वपूर्ण है। अगर खाते से आधार कार्ड लिंक नहीं है, तो भुगतान अटक सकता है। जिन किसानों के खाते और आधार लिंक ना हों, वह यह काम करा लें। किसान का पंजीयन उसी स्थिति में होगा, जब भू-अभिलेख में दर्ज खाते, खसरा, आधार कार्ड का मिलान हो, तभी किसान पंजीयन हो सकेगा। विसंगति होने पर सुधार कार्य तहसील कार्यालय से होगा।

बजट विकसित और आत्मनिर्भर भारत का विजन डॉक्यूमेंट है, आने वाले वर्षों में भारत की दिशा तय करने वाला बजट सिद्ध होगा : मंत्री सिलावट

केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर धार में पत्रकार वार्ता आयोजित

धार। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट ने केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर गुरुवार को भाजपा जिला कार्यालय धार में पत्रकार- वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष महंत निलेश भारती, धार विधायक नीना वर्मा,ग्रामीण जिला अध्यक्ष चंचल पाटीदार, जिला महामंत्री देवेंद्र सोनोने भाजपा जिला मीडिया प्रभारी संजय शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे।

कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में और वित मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्पों को सिद्ध करने वाला है। केंद्रीय बजट मध्यप्रदेश के आर्थिक-औद्योगिक और सामाजिक विकास का ऐतिहासिक अवसर सिद्ध होगा। पूंजीगत व्यय में वृद्धि, शहरों के विकास व लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम का विकास प्रदेश के लिए वरदान बनेगा। यह बजट सतत आर्थिक विकास के साथ जनअपेक्षाओं को पूरा करने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने समय-समय पर अपने निर्णयों से देश को सशक्त बनाने के साथ दुनिया को भारत की ताकत का अहसास कराया है। इस बजट के माध्यम से उद्योगों को बढ़ावा मिलने के साथ अलग-अलग क्षेत्रों में रोजगार के अनेक अवसर पैदा होंगे। यह केंद्रीय बजट सभी वर्गों की आशा-आकांक्षाओं को पूरा करने के साथ उन्हें सशक्त बनाने में निर्णायक सिद्ध होगा।

केंद्रीय बजट सिर्फ बजट नहीं है, यह विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत का विजन डॉक्यूमेंट है। यह आने वाले वर्षों में भारत की दिशा तय करने वाला बजट सिद्ध होगा। यह सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी और सर्वसमावेशी बजट है। बजट में तीन कर्तव्यों-आर्थिक विकास, जन-आकांक्षाओं की पूर्ति और 'सबका साथ, सबका

विकास' की परिकल्पना को साकार किया गया है। बजट में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है। केन्द्रीय बजट में राजकोषीय घाटा को 4.5 प्रतिशत से घटाकर 4.3 प्रतिशत तक लाने का रोडमैप तैयार किया है। देश के कुल कर्ज को जीडीपी के 56 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत तक लाने की भी योजना है। बजट में 7 हाई-स्पीड कॉरिडोर्स के निर्माण और 12.2 लाख करोड़ के कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रावधान किया गया है। सेमीकंडक्टर मिशन के लिए निवेश राशि को 22,500 करोड़ से बढ़ाकर 40,000 करोड़ करने का प्रस्ताव है।उन्होंने कहा कि इस बजट से मध्यप्रदेश को भी व्यापक लाभ होगा और यह बजट वर्ष 2047 के विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा।

यह बजट मध्यप्रदेश को सतत विकासशील राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में निर्णायक भूमिका अदा करेगा। बजट के प्रावधानों से मध्यप्रदेश में निवेश, उद्योग स्थापना, रोजगार सृजन, उत्पादन क्षमता, निर्यात उन्मुख विनिर्माण का बेहतर वातावरण तैयार होगा। केंद्रीय बजट मध्यप्रदेश के एमएसएमई सेक्टर के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। राज्य में उद्यमिता, स्वरोजगार तथा औद्योगिक विस्तार को मजबूती मिलेगी। मध्यप्रदेश के लघु एवं मध्यम उद्योग अधिक प्रतिस्पर्धी, आत्मनिर्भर और विस्तार उन्मुख बनेंगे। मध्यप्रदेश को आईटी, पर्यटन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाओं के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने में यह बजट महती भूमिका निभाएगा।

प्रधानमंत्री ने धार में पीएम मित्र पार्क की सौगात दी है, जिसके आधार पर हमारी सरकार मध्यप्रदेश वस्त्र उद्योग को बढ़ावा दे रही है। नए उद्योग लगाना अच्छी बात है, लेकिन जो चल रहे हैं उनका संवर्धन करना भी एक बड़ा कार्य है। हमारी सरकार इस क्षेत्र में भी कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने टियर-2 और टियर-3 शहरों के लिए भी पर्याप्त धनराशि दी गई है। मध्यप्रदेश में प्रमुख शहर संगठित और आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे और संरचना निवेश मॉडल मध्य प्रदेश के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। इस बजट से मध्यप्रदेश को भी व्यापक लाभ होगा और यह बजट वर्ष 2047 के विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा। यह बजट भारत को आने वाले वर्षों में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश तेजी से सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, और बजट 2026 उसी भरोसे और दूरदृष्टि का प्रमाण है। यह केंद्रीय बजट देश के आर्थिक विकास के साथ 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' की रफ्तार को भी दिखा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रस्तुत केंद्रीय बजट तात्कालिक प्रभाव से अधिक अगले 10-20 वर्षों में भारत की दिशा तय करने वाला है। यह बजट सशक्त भारत की नींव को और मजबूती प्रदान करेगा। हमारे प्रधानमंत्री ने देश को सशक्त बनाने के साथ दुनिया को भारत की ताकत का अहसास कराया है।भारत को आत्मनिर्भर बनाने, देशवासियों के कल्याण और मध्यम वर्ग को राहत देने वाले इस क्रांतिकारी बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का मध्यप्रदेशवासियों की ओर से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इस अवसर पर केंद्रीय बजट की जिला टोली से मोहित तातेड़ ,सुनील मोदी सोनू रघुवंशी ,भाजपा धार ग्रामीण जिला मीडिया प्रभारी विजय राठौर, मनोज सोलंकी कवि, मनोज चावला मंचासीन रहे।

'बेचारा सोहागपुर'

एक अदने बोहानी रेल्वे स्टेशन पर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन के स्टापेज को लेकर सोहागपुर में तीखी प्रतिक्रिया

सुबह सवेरे सोहागपुर

एक अदने सोहानी रेल्वे स्टेशन पर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन के स्टापेज को लेकर सोहागपुर में सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की जा रही हैं। उल्लेखनीय है सोहागपुर नगर के वाशिंदे लम्बे समय से इंटरसिटी एक्सप्रेस, ओवरनाइट एक्सप्रेस एवं श्रीधाम एक्सप्रेस के स्टापेज की मांग करते आ रहे थे। इन ट्रेनों के लिए सोहागपुर में आन्दोलन हुए, बाजार बंद, एवं धरना प्रदर्शन अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय के सामने हुए थे।तब तत्कालीन सांसद राव उदयप्रताप सिंह ने धरना स्थल पर आकर कहा था।कि मेरे होते हुए धरना प्रदर्शन करना नहीं चाहिए। तब उक्त आन्दोलन स्थगित कर दिया गया था। लेकिन देर सबेर लम्बे अरसे के बाद संयोग से श्रीधाम एक्सप्रेस का स्टापेज हो गया।आखिर सांसदों को बेरूखी सोहागपुर के वाशिंदों से क्यों है? यदि सोहागपुर पर दृष्टि घुमाई जाए तो सोहागपुर नर्मदापुरम की सबसे पुरानी तहसील है। वहीं सोहागपुर रेल्वे स्टेशन पर निगाह डाली जाए तो। इस स्टेशन पर सुविधाओं का अभाव है। न तो इसे अमृत भारत स्टेशन योजना का लाभ नहीं मिला। सोहागपुर के रेल्वे स्टेशन के एक नंबर प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो वर्तमान की स्थिति में नीचा है। वहीं दूसरी तरफ वाला प्लेटफॉर्म बेहद नीचा है। इस प्लेटफार्म पर बुजुर्ग, विकलांग, महिलाएं, बच्चों को इतनी तकलीफ़ होती जिसका अंदाजा न तो रेल्वे प्रशासन को है।न ही जनप्रतिनिधियों को है। हैरानी की बात यह है कि ट्रेनों के डिस्प्ले तक 21वीं सदी में नहीं लगाए गए हैं।जब ट्रेन आती है तब बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं अपने कोच के लिए दोड़ते नजर आते हैं। वहीं सोहागपुर के 15 वार्डों इन्दिरा वार्ड,तिलक वार्ड रेल्वे स्टेशन की दूसरी तरफ है।जब ट्रेन का समय होता है तब नागरिक, स्कूल जाने वाले बच्चों आधा आधा घंटे सम्पार गेट खुलने का इंतजार करते हैं।इस गेट के रास्ते बीसियों ग्राम के आदिवासी भी इसी रास्ते से आना जाना करते हैं। जनप्रतिनिधि एवं राजनैतिज्ञ आदिवासियों के हितों की बात तो मंचों से करते हैं। पर यथार्थ में उन्हें क्या देते हैं? सोहागपुर से लगा हुआ सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है। जिसमें देश के करीबन हर प्रदेश के वाशिंदों के अलावा विदेशी सैलानियों की भी आवक सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में है। उक्त नागरिक सोहागपुर या सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के लिए वापिस जाते समय क्या सुविधाओं को लेकर जाते होंगे।कि वाह क्या सोहागपुर का रेल्वे स्टेशन है? आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का सांसद चौधरी दर्शन सिंह को लिखित पत्र करीब करीब सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अलग अलग नागरिक ने डालकर टिप्पणियां लिखी। राकेश चौधरी ने व्यंग करते लिखा कि' बजाओ ताली बजाओ खाली 'एक सोशल मीडिया पर रेल मंत्री पत्र डालने वाले को भी नहीं बख्शा उसे लिखा अंकल ऐसे खुश हो रहे हो जैसे सोहागपुर में ट्रेन का स्टापेज हो गया है। गजेन्द्र चौधरी लिखते है 'सोहागपुर वालों बहुत बहुत बधाई'। अब तो सोहागपुर एवं आस-पास के नागरिकों को गंभीरतापूर्वक विचार करना पड़ेगा कि जनप्रतिनिधि हो तो अपने आस-पास का ? तभी कुछ बन पड़ेगा।

मंडीदीप विजेताः स्व. चौहान स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता के फाइनल मैच में मंडीदीप ने सोहागपुर को पराजित किया

सुबह सवेरे सोहागपुर। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व. प्रतापभानुसिंह चौहान स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता 2026 के फाइनल प्रतियोगिता का समापन समारोह क्षेत्रीय विधायक विजयपाल सिंह के मुख्य आतिथ्य एवं नगर पंचायत परिषद अध्यक्ष श्रीमति लता यशवंत पटैल की अध्यक्षता में पंडित जवाहरलाल नेहरु स्मृति महाविद्यालय परिसर में संपन्न हुआ। गरिमामय समारोह के विशिष्ट अतिथि समाजसेवी डॉ. अतुल सेठा नर्मदापुरम, समाजसेवी रोहित फौजदार नर्मदापुरम,समाजसेवी कायाकल्प डेरिया माखननगर थे। फाइनल प्रतियोगिता का मुकाबला मंडीदीप एवं सोहागपुर की टीम के मध्य हुआ। जिसमें मंडीदीप ने अपनी टीम के कौशल से उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन किया। फाइनल प्रतियोगिता देखने पहुंचे खेलप्रेमियों से जवाहरलाल नेहरू स्मृति महाविद्यालय परिसर खचा-खच भरा हुआ था। मंडीदीप ने प्रारंभ से आक्रामक खेल का प्रदर्शन किया। दर्शकों ने कलात्मक हांकी खेल देखकर तालियों से अभिवादन किया। आखिरकार मंडीदीप ने सोहागपुर को 6-2 से हराकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रताप भानु सिंह चौहान स्मृति अखिल भारतीय हांकी प्रतियोगिता के 61 वें साल में खिताब मंडीदीप ने अपने नाम कर लिया। इसके पूर्व अतिथियों का स्वागत किया गया। अतिथियों को जीप में बैठाकर ग्राउंड का भ्रमण कराया कराके खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। पूर्व नपाध्यक्ष अभिलाष सिंह चंदेल ने क्षेत्रीय विधायक विजयपालसिंह से आग्रह किया कि हॉकी टूर्नामेंट की राशि 31हजार से 51किए जाने पर सहमति

प्रदान की जाए। कार्यक्रम के अंत में विजेता मंडीदीप टीम को वरिष्ठ वकील जे पी माहेश्वरी द्वारा प्रदत्त पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष स्वर्गीय रामचन्द्र माहेश्वरी की स्मृति में ट्रॉफी एवं 31 हजार रूपये की राशि प्रदान की। उपविजेता सोहागपुर टीम को स्वर्गीय शरदचंद्र तिवारी स्मृति में प्रदत्त ट्रॉफी शिरीष तिवारी एवं सौरभ तिवारी 21 हजार रूपये की राशि एवं ट्रॉफी प्रदान की गई। वहीं उपविजेता टीम को आर जी चौबे एवं उपयंत्री ब्रजेश खानोंकर भी ट्राफी प्रदान की गई।

पुरस्कार वितरणः- विजेता टीम सोहागपुर को विधायक ठाकुर विजयपाल सिंह राजपूत द्वारा 31 हजार रुपये की नगद राशि प्रदान की गई। वहीं स्व. रामचन्द्र महेश्वरी की स्मृति में ट्रॉफी गोपाल महेश्वरी द्वारा दी गई। सभी खिलाड़ियों को ट्रॉफी गोपाल चौबे एवं सब इंजीनियर बृजेश खानोरकर द्वारा प्रदान की गई।अन्य व्यक्तिगत पुरस्कारः- बेस्ट गोलकीपरः रोनीत राय (सोहागपुर)

बेस्ट फॉरवर्डः सत्यम (मंडीदीप) – नप्पू भैया की स्मृति में

बेस्ट डिफेंडरः हर्ष डोंगरे (सोहागपुर)

बेस्ट कमेंट्रीः आनंद पाराशर

बेस्ट अंपायरः शिवम, रवि हरदुआ, जय सिंह भदौरिया, नीरज, विशाल एवं मौर्य, योगदानः-मे शानदार ग्राउंड निर्माण में सहयोग देने वाले रमेश प्रजापति, शनी दादा, निलेश एवं फितुरी दादा तथा सफाई व्यवस्था में योगदान देने वाले रंजीत धोलपुरिया, सुजीत, शिवम, मुकेश डागोर, नीलेश कलोसिया एवं सुनील घावरी को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, खेल समिति पदाधिकारी, कैलाश पालीवाल, कन्नूलाल अग्रवाल, हमीर सिंह चंदेल, जयप्रकाश महेश्वरी, मंगल सिंह अधिवक्ता, भानु तिवारी,, बी.के. शर्मा, हरिहर सिंह अधिवक्ता, बीएमओ रेखा सिंह उपस्थित थे। वहीं आयोजन समिति के अध्यक्ष जयराम रघुवंशी, संयोजक शंकरलाल मालवीय एवं अश्विनी सरोज, सचिव पवन सिंह चौहान सहित अभिषेक चौहान, सौरभ तिवारी, अख्तर खान, दादूराम कुशवाहा, एकम राजपूत, दिलीप परदेसी, अभिनव पालीवाल, शेख आरिफ, रज्जन यादव, अंकुश जैसवाल एवं गब्बी एडवर्ड को सफल आयोजन हेतु सम्मानित किया गया।

संक्षिप्त समाचार

कलेक्टर श्री सूर्यवंशी की अध्यक्षता में जिला कौशल विकास समिति की बैठक आयोजित

बैतूल (निप्र)। कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला कौशल विकास समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने सभी संबंधित विभागों को कार्य में तेजी लाने और निर्धारित लक्ष्यों को समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के अंतर्गत श्रम विभाग, उद्योग विभाग एवं रोजगार अधिकारी को निर्देशित किया कि योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए तथा जिले के अधिक से अधिक ईपीएफओ पंजीकृत प्रतिष्ठानों को योजना से जोड़ा जाए, ताकि युवाओं को रोजगार और प्रशिक्षण के बेहतर अवसर मिल सकें। बैठक में शिक्षा विभाग को निर्देश देते हुए कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने कहा कि विद्यार्थियों को व्यावसायिक भ्रमण के तहत अधिक से अधिक आईटीआई का भ्रमण कराया जाए। इससे छात्र व्यावसायिक शिक्षा के प्रति जागरूक होंगे और आईटीआई में आगामी सत्र के लिए शत-प्रतिशत प्रवेश लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा।

निलंबित लाइसेंस वाली दुकानों की जानकारी सार्वजनिक करें : कलेक्टर

विदिशा (निप्र)। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने आज आयोजित लंबित आवेदनों की समीक्षा बैठक में पारदर्शिता और जनहित को प्राथमिकता देते हुए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि जिले में जिन खाद-बीज एवं मेडिकल स्टोर की दुकानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, उनकी जानकारी संबंधित दुकानों पर फ्लेक्स बोर्ड के माध्यम से प्रदर्शित की जाए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि यह कदम आम नागरिकों को जागरूक करने और अनधिकृत रूप से संचालित गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। फ्लेक्स के माध्यम से लाइसेंस निलंबन की स्थिति स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होने से उपभोक्ताओं को सही जानकारी मिलेगी और वे सुरक्षित निर्णय ले सकेंगे। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि निलंबित दुकानों की अद्यतन सूची तैयार कर उसका सत्यापन करें तथा नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी कहा गया कि निरीक्षण कार्य नियमित रूप से जारी रखा जाए, ताकि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर समय पर कार्रवाई हो सके। कलेक्टर ने कहा कि जनस्वास्थ्य एवं कृषि से जुड़े क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य जनता को सुरक्षित और गुणवत्ता युक्त सेवाएं उपलब्ध कराना है।

रामलीला मेले में खाद्य प्रतिष्ठानों की सघन जांच, स्वच्छता व गुणवत्ता पर सख्त निर्देश

विदिशा (निप्र)। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा रामलीला मेले में संचालित खाद्य प्रतिष्ठानों का आज सघन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण का उद्देश्य मेले में आने वाले नागरिकों को स्वच्छ एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना रहा। निरीक्षण के दौरान चाट एवं नाश्ता दुकानों पर विशेष रूप से साफ-सफाई बनाए रखने, खाद्य पदार्थों को स्वच्छ वातावरण में तैयार करने तथा ग्राहकों को शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। दुकानदारों को खाद्य सामग्री को ढककर रखने और व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन करने की भी हिदायत दी गई। अधिकारियों द्वारा पैकेज्ड फूड सामग्री की एक्सपायरी डेट की जांच की गई और स्पष्ट निर्देश दिए गए कि किसी भी स्थिति में एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री का उपयोग या विक्रय न किया जाए। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। प्रशासन ने कहा कि जनस्वास्थ्य सर्वोपरि है और ऐसे निरीक्षण आगे भी निरंतर जारी रहेंगे, ताकि मेलों और सार्वजनिक आयोजनों में खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

जिले में दिव्यांग बच्चों की स्क्रीनिंग हेतु 16 से 27 फरवरी तक आयोजित होंगे विशेष शिविर

नर्मदापुरम (निप्र)। जिले में दिव्यांग बच्चों की शीघ्र पहचान (स्क्रीनिंग) कर उन्हें त्वरित रूप से दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं यूडीआईडी कार्ड जारी करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा विशेष शिविरों की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। इन शिविरों के माध्यम से दिव्यांग बच्चों की शीघ्र स्क्रीनिंग कर त्वरित दिव्यांग प्रमाण पत्र यू डी आई डी जारी किए जाएंगे। जनपद पंचायत एवं नगरपालिका पिपरिया एवं, साडा, केन्ट पचमढी के लिए शिविर का आयोजन 16 फरवरी 2026 को जनपद पंचायत पिपरिया प्रांगण में किया जायेगा। इसी प्रकार जनपद पंचायत एवं नगर परिषद बनखेड़ी अंतर्गत जनपद पंचायत बनखेडी में 17 फरवरी को, जनपद पंचायत एवं नगर परिषद सोहागपुर अंतर्गत जनपद पंचायत सोहागपुर में 18 फरवरी को, जनपद पंचायत एवं नगर परिषद माखननगर अंतर्गत जनपद पंचायत माखननगर में 19 फरवरी को, नगरपालिका परिषद इटारसी अंतर्गत नगरपालिका इटारसी में 20 फरवरी को, जनपद पंचायत केसला अंतर्गत जनपद पंचायत केसला में 23 फरवरी को, जनपद पंचायत एवं नगरपालिका सिवनी मालवा अंतर्गत जनपद पंचायत सिवनीमालवा में 24 फरवरी को एवं जनपद पंचायत एवं नगरपालिका नर्मदापुरम में शिविर का आयोजन जिला पंचायत नर्मदापुरम में 27 फरवरी 2026 को किया जायेगा।

सभी कलेक्टर्स रोजगार उद्योग निवेश संबंधी बिंदुओं की समीक्षा करे : कमिश्नर

नर्मदापुरम (निप्र)। नर्मदापुरम संभाग कमिश्नर श्री कृष्ण गोपाल तिवारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर को निर्देश दिए की कलेक्टर कान्फ्रेंस अक्टूबर 2025 की कार्यवाई विवरण में उल्लेखित थीम रोजगार उद्योग एवं निवेश के संबंध में सभी कलेक्टर्स आवश्यक कार्यवाई करें एवं रोजगार उद्योग और निवेश में उल्लेखनीय प्रगति लाए। कमिश्नर ने निर्देश दिए कि फूड प्रोसेसिंग धार्मिक क्षेत्र पर्यटन के क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगारो का सृजन किया जाए, एक जिला एक उत्पाद के तहत जिले के प्रोडक्ट को पर्याप्त मार्केटिंग मिले, उत्पादन का पर्याप्त प्रचार प्रसार किया जाए साथ ही लघु एवं कुटीर उद्योग को प्राथमिकता देते हुए इसमें निवेश एवं रोजगार के अवसर सृजित किए जाएं। कमिश्नर ने निर्देश दिए कि डीएलसीसी एवं डीएलआरसी की बैठक प्रति माह नियमित रूप से आयोजित की जाए। उन्होंने निर्देश दिए की बंद पड़े उद्योगों की भूमि का भी अन्य शासकीय प्रयोजन में उपयोग किया जाए। कमिश्नर ने निर्देश दिए की कौशल विकास की जिला स्तरीय समिति की बैठक भी नियमित रूप से आयोजित की जाए साथ ही उद्योगों की स्थापना के लिए यदि शासकीय भूमि की आवश्यकता होती है तो भू अर्जन की प्रक्रिया भी समय पर पूरी की जाए। कमिश्नर ने नर्मदापुरम बैतूल एवं हरदा के कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि

प्रधानमंत्री विश्वकर्म योजना को टॉप प्राथमिकता में रखते हुए सभी बैंकर्स को निर्देश दें कि वे हितग्राहियों के ऋण प्रकरण प्राथमिकता से स्वीकृत करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि युवाओं को स्वरोजगारों के लिए ऋण की राशि बैंक से समय सीमा में प्राप्त हो जाए। कमिश्नर ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की नियमित मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए और कहां की इस योजना के तहत शासन द्वारा दिए गए सभी लक्ष्य की पूर्ति समय सीमा में कर ली जाए। कमिश्नर ने कलेक्टर कान्फ्रेंस की कार्रवाई विवरण में उल्लेखित थीम स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित 22 पैरामीटर जिनमें पांच पैरामीटर महिला एवं बाल विकास से संबंधित है कि नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने कहा कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतिदिन इन 22 पैरामीटर की मॉनिटर करें और इन 22 पैरामीटर में उल्लेखित प्रगति से प्रतिदिन कलेक्टर को अवगत कराए। कलेक्टर भी निरंतर मॉनिटरिंग कर इन क्षेत्रों में विशेष प्रगति लाकर जिले की रैंकिंग में आवश्यक सुधार करें। कमिश्नर ने निर्देश दिए की 03 से 06 आयु के बच्चे

सभी कलेक्टर्स पीएम विश्वकर्मा योजना को पहली प्राथमिकता में रखें स्वास्थ्य के 12 पैरामीटर की प्रतिदिन मॉनिटरिंग की जाए

माह में कम से कम 21 दिन आंगनवाड़ी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। बताया गया की नर्मदापुरम जिले में लगभग 82% कुपोषित बच्चों का पंजीयन किया गया है और उन सभी बच्चों को स्वास्थ बच्चों की श्रेणी में लाने के लिए उनको पर्याप्त पोषण आहार देकर उनके स्वास्थ्य की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। कमिश्नर श्री तिवारी ने बैंक आधारित विभिन्न विभाग जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य, उघानिकी, एमएसएमई, जनजातिय कार्य विभाग, अनुसूचित जाति विकास निगम, नगरीय प्रशासन विभाग की हितग्राही मूलक योजनाओं की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने निर्देश दिए की बैंक आधारित विभाग अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन में पीछे ना रहे अपितु बैंक आधारित योजनाओं में स्वरोजगार के लिए बैंक से हितग्राहियों को ऋण राशि का लाभ दिलाने में स्वीकृति प्राप्त करें। कमिश्नर ने निर्देश दिए कि टंट्या मामा योजना एवं बिरसा मुंडा योजना में विशेष तौर पर शत प्रतिशत राशि का वितरण कर युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण राशि स्वीकृत कराकर शत प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने निर्देश दिए की विशेष तौर पर मत्स्य विभाग अपनी योजनाओं में शत प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति करें। बताया गया कि स्मार्ट फिश पार्लर के लिए चिन्हित स्थानों में से कुछ स्थानों में परिवर्तन किया जा रहा है।

फूलों की खेती से किसान श्री राजकुमार को हो रहा कई गुना लाभ

किसानों के लिए लाभकारी व्यवसाय है फूलों की खेती

रायसेन (निप्र)। प्रदेश में उद्यानिकी विभाग की योजनाओं के सहयोग से किसान अब पारंपरिक फसलों को छोड़कर फूलों की खेती की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे उन्हें कई गुना अधिक लाभ हो रहा है। रायसेन जिले में भी फूलों की खेती किसानों के लिए लाभकारी व्यवसाय बनकर उभरी है, जिससे वे पारंपरिक फसलों की तुलना में कई गुना अधिक लाभ कमा रहे हैं।

रायसेन जिले के औबेदुल्लागंज विकासखण्ड के ग्राम गुदावल के किसान श्री राजकुमार अहिरवार भी उन प्रगतिशील किसानों में शामिल हैं जिन्होंने पारम्परिक फसल गेहूँ/चना, सोयाबीन की खेती को छोड़कर फूलों की खेती करना शुरू किया और कहीं अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। किसान श्री राजकुमार अहिरवार ने बताया कि पहले वह पारम्परिक फसलों की खेती करते थे, जिससे उन्हें बहुत कम लाभ होता था। जब उन्होंने फूलों की खेती से होने वाले लाभ के बारे में सुना तो उन्होंने उद्यानिकी विभाग में सम्पर्क किया। उन्होंने पहले फूलों की खेती कर रहे किसानों के खेतों का भी भ्रमण किया। किसान श्री राजकुमार द्वारा उद्यानिकी विभाग की योजना की मदद से 2500 वर्ग मीटर क्षेत्र में पॉली हाउस का निर्माण किया गया, इसके लिए उन्हें अनुदान सहायता भी प्रदान की गई। उन्होंने पॉली हाउस में जरबेरा फूलों की खेती शुरू की। श्री राजकुमार अहिरवार ने बताया कि वह लाल, पीले, गुलाबी और नारंगी रंग के जरबेरा फूलों का उत्पादन ले रहे हैं।

कोटपा एक्ट के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु जिला प्रवर्तन दस्ते का प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित

नर्मदापुरम (निप्र)। तम्बाकू मुक्त समाज की दिशा में जिला प्रशासन एवं राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत कोटपा एक्ट के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु जिला प्रवर्तन दस्ते का एक दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित हुई। कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना के दिशानिर्देश और सीएमएचओ डॉ. नरसिंह गेहलोत के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यशाला में जिला नोडल अधिकारी डॉ. रजनी कुशवाहा ने पीपीटी प्रजेंटेशन के माध्यम से उपस्थित सदस्यों को कोटपा अधिनियम-2003 के तहत गठित जिला प्रवर्तन दस्ते की भूमिका और

जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी दी। कार्यशाला में पुलिस, स्वास्थ्य, खाद्य, शिक्षा, जिला पंचायत विभाग के अधिकारियों को तम्बाकू नियंत्रण कानूनों, चालान प्रक्रिया और प्रवर्तन के दौरान अपनाई जाने वाली समस्त कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में प्रशिक्षित किया गया। युवा तंबाकू नियंत्रण अभियान 3.0 के तहत युवाओं को तंबाकू के दुष्प्रभावों से बचाव के लिये प्रवर्तन दल द्वारा क्षेत्रों का निरीक्षण किया जायेगा। वरिष्ठ अधिकारियों ने निर्देश दिये हैं कि दस्ते द्वारा नियमित छापेमारी की जाये तथा उल्लंघन कर्ताओं के विरूद्ध तम्बाकू नियंत्रण से दिशानिर्देशों के अनुसार तत्काल कड़ी दंडात्मक कार्यवाही की जाये। प्रशिक्षण में जिला मीडिया प्रभारी स्वास्थ्य सुनील साहू, खाद्य निरीक्षण श्री राणा, एएसआई गौरीशंकर सिंह, जिला पंचायत से पीओ प्रीति वरकडे, शिक्षा विभाग से राजेन्द्र प्रसाद नामदेव प्रतिभागी रहे। पिछले माह जिला मुख्यालय नर्मदापुरम सहित इटारसी एवं माखननगर में जिला प्रवर्तन दस्ते द्वारा कोटपा एक्ट के अंतर्गत नागरिकों में जन जागरूकता लाने हेतु तम्बाकू उत्पादों के दुष्प्रभाव बताये गये तथा उल्लंघन कर्ताओ के खिलाफ चालानी कार्यवाही की गई।

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पहल : ड्राइविंग प्रशिक्षण उपरांत लाइसेंस बनाए गए

नर्मदापुरम (निप्र)। महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने की दिशा में इटारसी स्थित नई दिशाएँ नारी विकास समिति द्वारा सराहनीय पहल की गई है। संस्था द्वारा लगभग 52 महिलाओं को 45 दिवसीय निःशुल्क चार पहिया वाहन संचालन का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) श्रीमती रिंकू शर्मा द्वारा सभी प्रशिक्षित महिला चालकों को सुरक्षित ड्राइविंग के महत्वपूर्ण गुर सिखाए गए। इस दौरान मोटर व्हीकल एक्ट से संबंधित प्रावधानों, सड़क सुरक्षा नियमों तथा यातायात नियमों के उल्लंघन पर की जाने वाली चालानी कार्रवाई के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। आरटीओ ने महिलाओं को वाहन चलाते समय सतर्कता, गति नियंत्रण, ट्रैफिक सिग्नल का पालन, सीट बेल्ट के उपयोग एवं पैदल यात्रियों के प्रति संवेदनशीलता बरतने की विशेष सलाह दी। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल स्वयं की नहीं, बल्कि अन्य नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ी जिम्मेदारी है। उल्लेखनीय है कि महिलाओं को निशुल्क हेलमेट प्रदान किए जायेंगे। प्रशिक्षण प्राप्त कर महिलाओं में विशेष उत्साह देखा गया। सभी प्रतिभागियों ने आरटीओ द्वारा बताए गए नियमों का पालन करने और जिम्मेदार चालक बनने का आश्वासन दिया।

महाशिवरात्रि पर भोजपुर में होगा तीन दिवसीय 'महादेव-भोजपुर महोत्सव'

शिव-साधना, लोकआस्था और कला-सौंदर्य का दिव्य संगम

रायसेन (निप्र)। महाशिवरात्रि के पावन पर्व के अवसर पर संस्कृति विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा शिव-साधना, लोकआस्था एवं कला-सौंदर्य के समन्वित उत्सव के रूप में ऐतिहासिक भोजपुर शिव मंदिर प्रांगण में तीन दिवसीय 'महादेव भोजपुर महोत्सव' का आयोजन 15 से 17 फरवरी 2026 तक प्रतिदिन सायं 6.30 बजे से किया जाएगा। जिला प्रशासन रायसेन के सहयोग से आयोजित यह महोत्सव शिव-शक्ति, लोकपरंपरा और सांस्कृतिक चेतना का भव्य उत्सव होगा। संस्कृति संचालक श्री एनपी नामदेव ने बताया कि यह महोत्सव भोजपुर की ऐतिहासिक एवं आध्यात्मिक धरोहर को सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के माध्यम से राष्ट्रीय पटल पर प्रतिष्ठित करने का सशक्त प्रयास है। लोकगायन, लोकनृत्य, नृत्य-नाटिका, सुगम संगीत एवं काव्य-पाठ के माध्यम से शिव महिमा, लोकसंवेदना और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों की सजीव प्रस्तुति की जाएगी। महोत्सव के प्रथम दिवस 15 फरवरी को सागर के ऋषि विश्वकर्मा द्वारा प्रस्तुत लोकगायन से कार्यक्रम का शुभारंभ होगा, जो मंदिर प्रांगण को भक्तिरस से अनुप्राणित करेगा। इसके पश्चात सागर के उमेश नामदेव द्वारा प्रस्तुत बधाई एवं बरेदी लोकनृत्य में लोकजीवन की जीवंत छवियाँ साकार होंगी। संध्या का विशेष आकर्षण मुंबई के सुप्रसिद्ध भजन गायक श्री लखबीर सिंह लक्खा का भक्ति गायन होगा, जो श्रद्धालुओं को शिवभक्ति में लीन कर देगा। महोत्सव के द्वितीय दिवस 16 फरवरी को भोपाल की शीला त्रिपाठी द्वारा लोकगायन की प्रस्तुति दी जाएगी। इसके उपरांत मुंबई की भावना शाह एवं साथी कलाकारों द्वारा शिव महिमा पर आधारित नृत्य-नाटिका का मंचन किया जाएगा, जिसमें नृत्य, भाव और संगीत का प्रभावशाली समन्वय दर्शकों को आध्यात्मिक अनुभूति से भर देगा। दूसरे दिन का समापन मुंबई की सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका महालक्ष्मी अय्यर की मधुर सुगम संगीत प्रस्तुति से होगा। महोत्सव के अंतिम दिवस 17 फरवरी को भोपाल के बलराम पुरोहित द्वारा लोकगायन प्रस्तुत किया जाएगा। इसके पश्चात भोपाल की आकृति जैन एवं साथी कलाकारों द्वारा प्रस्तुत शिव-केंद्रित नृत्य-नाटिका वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से आलोकित करेगी। समापन अवसर पर आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में देश के प्रतिष्ठित कविकृदिल्ली के अशोक चक्रधर, मुंबई के दिनेश बावरा, आगरा के प्रताप फौजदार, दिल्ली के गजेन्द्र सोलंकी, आगरा की रुचि चतुर्वेदी, मथुरा की पूनम वर्मा तथा दिल्ली की मनु वैशाली अपनी सशक्त, संवेदनशील एवं भावपूर्ण रचनाओं से काव्यरस की अविरल धारा प्रवाहित करेंगे। यह महोत्सव न केवल शिवभक्ति और लोकपरंपराओं का उत्सव है, बल्कि जनसामान्य को भारतीय सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम भी है। संस्कृति विभाग द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे इस सांस्कृतिक महोत्सव में सहभागिता कर शिव-साधना और कला-सौंदर्य के इस दिव्य संगम का साक्षी बनें।

बैतूल में खेलो इंडिया महिला हॉकी चयन ट्रायल का आयोजन

बैतूल (निप्र)। मध्य प्रदेश शासन के खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा खेलो इंडिया जनजाति महिला हॉकी चयन ट्रायल का आयोजन सोमवार को स्थानीय मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम बैतूल में किया गया। चयन ट्रायल प्रातः 9 बजे से प्रारंभ हुआ। जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी श्रीमती पूजा कुरील ने बताया कि चयन प्रक्रिया में मध्य प्रदेश के रायसेन, मंडला, बालाघाट, सिवनी, बैतूल, देवास एवं उमरिया जिलों से आई लगभग 35 महिला खिलाड़ियों ने भाग लेकर अपने खेल कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। चयनित खिलाड़ियों से मध्य प्रदेश की टीम का गठन किया जाएगा, जो आगामी प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेगी। इस अवसर पर हॉकी संघ बैतूल के अध्यक्ष श्री अक्षय वर्मा, श्री जगेंद्र तोमर, श्री टोप्पो एवं श्री विनय यादव विशेष रूप से उपस्थित रहे। खिलाड़ियों के दस्तावेज सत्यापन का कार्य श्री राम नारायण शुक्ला एवं श्री राधेलाल बनखेड़ द्वारा किया गया, जबकि खेल योग्यता का मूल्यांकन तपेश साहू, अजय मिश्रा एवं जगेंद्र तोमर द्वारा किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में खेल विभाग के श्री हेमंत विश्वकर्मा, योगिता शैलेन्द्र शर्मा एवं समन्वयक श्रीमती ललिता धुर्वे का सहयोग रहा।

जिला पंचायत अध्यक्ष ने दोपहिया वाहन रैली को हरी झण्डी दिखाकर किया रवाना

रायसेन (निप्र)। राज्य शासन द्वारा वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसके लिए किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है।

इसी कड़ी में मंगलवार को रायसेन में कृषि विभाग द्वारा दोपहिया वाहन रैली आयोजित की गई, जिसे जिला पंचायत अध्यक्ष श्री यशवंत मीणा तथा अपर कलेक्टर श्री मनोज उपाध्याय द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर से हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया। यह वाहन रैली कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर से प्रारंभ होकर नगर में मुख्य मार्ग से होते हुए कृषि उपज मंडी पहुंची। वाहन रैली के माध्यम से किसानों को खेती की नवीन तकनीकों को अपनाकर फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए जागरूक किया गया। वाहन रैली में किसान और कृषि विभाग के अधिकारी-कर्मचारी सम्मिलित हुए। इस अवसर पर उप संचालक कृषि श्री केपी भगत, सहायक संचालक श्री दुष्यंत कुमार धाकड़ सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। जिले में किसानों के लिए कृषि एवं कृषि से संबंधित विभागों की योजनाओं का प्रचार-प्रसार कृषि रथ के माध्यम से निरंतर ग्राम पंचायतों में किया जा रहा है।

नरवाई प्रबंधन के लिए जागरूकता के साथ दंडात्मक कार्रवाई की जाए : कलेक्टर श्री सूर्यवंशी

बैतूल (निप्र)। कलेक्टर श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी की अध्यक्षता में कृषि एवं संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा प्रस्तुत नरवाई प्रबंधन की रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने कृषि विभाग के अमले को निर्देशित किया कि नरवाई प्रबंधन के लिए व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने के साथ-साथ नियमों का उल्लंघन करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने नरवाई प्रबंधन के लिए आवश्यक कृषि यंत्रों जैसे स्ट्रॉ रीपर, रीपर कंबाइंडर आदि के पंजीयन को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने बिना एसएमएस के कंबाइंड हार्वेस्टर के संचालन पर रोक लगाने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने कहा कि इस विषय पर किसानों के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जाएं तथा जिले में नरवाई जलाने की घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए लक्ष्य बढ़ाने के लिए वरिष्ठ कार्यालय से आवश्यक समन्वय किया जाए।

उन्होंने नरवाई जलाने पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने के निर्देश भी उप संचालक कृषि को दिए। बैठक में कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने जिले में प्राकृतिक खेती से संबंधित संचालित गतिविधियों की भी समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों को प्राकृतिक खेती के लाभों के प्रति जागरूक किया जाए।

ई-टोकन के माध्यम से हो खाद वितरण

कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने जिले में खाद की उपलब्धता एवं वितरण की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने सहकारिता, कृषि विभाग एवं मार्कफेड को निर्देश दिए कि ई-टोकन प्रणाली के माध्यम से ही खाद का वितरण सुचारू रूप से किया जाए, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। इसके साथ ही कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने प्रेशराइज्ड इरिगेशन योजनाओं में पंजीयन बढ़ाने के लिए उप संचालक कृषि को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में मत्स्य और पशुपालन विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं की भी विस्तार से समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों केसीसी के प्रकरणों में शत प्रतिशत उपलब्धि हासिल करने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में कृषि उपसंचालक श्री आनंद कुमार बड़ोनिया सहायक कृषि यंत्री डॉ. प्रमोद कुमार मीणा, सहायक संचालक मत्स्य श्री कमलेश खरे, डीएमओ श्री प्रदीप गढ़ेवाल, पशुपालन विभाग से श्री कमलेश डेहरिया सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

डॉ. जवाहर कर्नावट इजिप्ट सम्मेलन में व्याख्यान देंगे

भोपाल। प्रदेश के प्रख्यात लेखक-वक्ता तथा भारत सरकार द्वारा विश्व हिंदी सम्मान से अलंकृत डॉ. जवाहर कर्नावट को इजिप्ट की राजधानी काहिरा में विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित अफ्रीका-भारत

अंतरराष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में विशिष्ट वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया है। भारतीय दूतावास, काहिरा द्वारा 8-9 फरवरी को आयोजित इस सम्मेलन में डॉ. कर्नावट 'हिंदी : विभिन्न क्षेत्रों में सांस्कृतिक संपर्क के लिए सेतु' विषय पर वक्तव्य देंगे। इस सम्मेलन में अफ्रीकी देशों के हिंदी विद्वान और शिक्षक प्रमुखता से भागीदारी करेंगे। डॉ. कर्नावट इस सम्मेलन के पश्चात कुवैत की संस्था 'अंजुमन-ए-पंखुड़ी' द्वारा 11 फरवरी को आयोजित कार्यक्रम में भी विशिष्ट अतिथि होंगे। उल्लेखनीय है कि डॉ. कर्नावट रबींद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के हिंदी केंद्र के निदेशक तथा प्रवासी भारतीय शोध केंद्र के सलाहकार भी हैं।

होली पर राजधानी-रीवा रूट के यात्रियों को राहत

रानी कमलापति और भोपाल से 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें, दानापुर भी जाएगी

भोपाल (नप्र)। होली त्योहार के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन ने रानी कमलापति और भोपाल से रीवा के लिए कुल चार जोड़ी होली स्पेशल ट्रेनों के संचालन का फैसला किया है। इसके अलावा रानी कमलापति-दानापुर के बीच भी द्वि-साप्ताहिक होली स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। इन ट्रेनों से सतना, कटनी, सागर, बीना

सहित मध्यप्रदेश के कई जिलों के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा।

रानी कमलापति-रीवा के बीच दो जोड़ी स्पेशल ट्रेनें

रीवा-रानी कमलापति साप्ताहिक स्पेशल (01-01 ट्रिप)

गाड़ी संख्या 02192 शनिवार 28 फरवरी को दोपहर 12:30 बजे रीवा से रवाना होकर रात 9:15 बजे रानी कमलापति पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 02191 उसी दिन रात 10:15 बजे रानी कमलापति से चलकर अगले दिन सुबह 7:30 बजे रीवा पहुंचेगी।

रीवा-रानी कमलापति द्वि-साप्ताहिक स्पेशल (02-02 ट्रिप)

गाड़ी संख्या 02186, 2 और 3 मार्च को दोपहर 12:30 बजे रीवा से प्रस्थान करेगी और रात 9:15 बजे रानी कमलापति पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 02185 रात 10:15 बजे रानी कमलापति से चलकर सुबह 7:30 बजे रीवा पहुंचेगी। इन दोनों ट्रेनों का ठहराव सतना, मैहर, कटनी मुड़वारा, दमोह, सागर, बीना और विदिशा स्टेशनों पर रहेगा।

'ग्रुमिंग लव जिहाद'...रेप किया, बुर्के में भगाया, दोस्त को सौंपा

प्रेमजाल में फंसाकर नाबालिग को उज्जैन से ले गया, मुस्लिम बस्ती में मिली, नाबालिग आरोपी गिरफ्तार

उज्जैन (नप्र)। उज्जैन में चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र से लापता हुई 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को पुलिस ने 48 घंटे के भीतर इंदौर के आजाद नगर इलाके से बरामद कर लिया है। लड़की एक नाबालिग लड़के के साथ मिली, और रेस्क्यू के वक्त भी वह बुर्का पहने हुए थी। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने रेप की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। मामले में और आरोपियों के जुड़ने की संभावना जताई गई है।

सीसीटीवी में पीछा करता दिखा युवक- पुलिस के मुताबिक 2 फरवरी की सुबह करीब 10:47 बजे लड़की उस वक्त घर से निकली, जब उसकी मां काम पर जा चुकी थी। सीसीटीवी फुटेज में सामने आया है कि मोईन नामक युवक एक्टिवा से उसका पीछा करता हुआ नजर आया। घर से कुछ दूरी पर उसे एक्टिवा पर बैठाया गया।

टावर पर उतारा, वहां इंतजार कर रहा था नाबालिग बॉयफ्रेंड- जांच में सामने आया कि मोईन ने लड़की को टावर के पास उतारा, जहां पहले से उसका नाबालिग बॉयफ्रेंड मौजूद था। इसके बाद दोनों बस स्टैंड के जरिए इंदौर पहुंचे और आजाद नगर इलाके में रुके।

3 फरवरी को एफआईआर, 4 फरवरी को इंदौर से रेस्क्यू- 3 फरवरी को चिमनगंज मंडी थाने में गुमशुदगी दर्ज हुई। एफआईआर के बाद पुलिस ने परिवार, सहेलियों और संदिग्धों से पूछताछ की। मोबाइल चैट और तकनीकी इनपुट के आधार पर 4 फरवरी की शाम को पुलिस ने लड़की को इंदौर से बरामद कर लिया।

पीड़िता ने रेप का आरोप लगाया, मेडिकल कराया गया- पुलिस के अनुसार पीड़िता ने बयान में दुष्कर्म की बात कही, जिसके बाद उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया। पीड़िता के 164 के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किए जाने हैं। मेडिकल और एफएसएल रिपोर्ट की विस्तृत जानकारी आना बाकी है।

ब्रेकअप कर अपने ही दोस्त को उसके पीछे लगाया- पुलिस जांच में सामने आया है कि करीब 6 महीने पहले अहमद नगर निवासी एक नाबालिग ने पीड़िता से संपर्क बनाया। शुरुआती जांच के अनुसार बाद में दोनों के बीच दूरी बढ़ी और आरोपी ने अपने एक नाबालिग दोस्त को लड़की के संपर्क में बनाए रखा। मोबाइल चैट की जांच में यह भी सामने आया है कि पीड़िता की कुछ सहेलियों की भूमिका ब्रेनवॉश और संपर्क बनाए रखने में रही, जिसकी जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि इन बिंदुओं के आधार पर आगे और आरोपियों के नाम जुड़ सकते हैं।

एआई आधारित डिजिटल क्रॉप सर्वे और फार्मर रजिस्ट्री से पारदर्शी व प्रमाणिक कृषि डेटा व्यवस्था हुई स्थापित

किसानों को सशक्त बनाने किया जा रहा है तकनीक का प्रभावी उपयोग : मुख्यमंत्री

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि किसानों को सशक्त बनाने और कृषि व्यवस्था को आधुनिक स्वरूप देने के लिए तकनीक का प्रभावी उपयोग किया जा रहा है। एआई आधारित डिजिटल क्रॉप सर्वे और फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से राज्य में ग्रामीण डेटा प्रणाली को एक नई दिशा प्रदान की गई है। उन्नत तकनीक, पारदर्शी डेटा प्रबंधन और केंद्र-राज्य समन्वय से यह पहल किसानों के हित में मजबूत डिजिटल

● **म.प्र. बना फार्मर रजिस्ट्री के शत-प्रतिशत अनुपालन वाला पहला राज्य**

आधार तैयार कर रही है। इससे किसानों को योजनाओं का वास्तविक लाभ सुनिश्चित होगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से खेत पर उपस्थित होकर फसल की फोटो लेकर जानकारी सुरक्षित की जा रही है, जिससे फसल संबंधी डेटा पूरी तरह प्रमाणिक हो रहा है। जियो-फेंसिंग तकनीक से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सर्वे केवल वास्तविक खेत स्थल पर ही किया जाए। सर्वे डेटा का त्रिस्तरीय सत्यापन एआई/एमएल सिस्टम और पटवारी स्तर पर किया जा रहा है। अन्य विभागों द्वारा

भी इस डेटा का प्रभावी उपयोग किया जा रहा है। डीसीएस डेटा के आधार पर उपार्जन पंजीयन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि इंटरनेट उपलब्ध न होने की स्थिति में भी सर्वे की विश्वसनीयता बनी रहे। सर्वे के दौरान ली गई फोटो की प्रामाणिकता और सही लोकेशन की पुष्टि प्रणाली द्वारा की जाती है। सर्वे केवल निर्धारित समयावधि में ही संभव है और समय सीमा के बाहर या मोबाइल समय में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ होने पर सर्वे स्वतः रुक जाता है। एआई या एमएल एल्गोरिदम के माध्यम से डेटा का क्रॉस-वेरिफिकेशन कर मानवीय त्रुटियों की संभावना को न्यूनतम किया गया है। फसल क्षेत्र, उत्पादन अनुमान और योजनाओं के क्रियान्वयन में डेटा-ड्रिवन निर्णय लिए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री को एकीकृत डिजिटल प्रणाली के रूप में विकसित किया गया है। इसमें किसानों की पहचान, भूमि विवरण और योजना संबंधी जानकारी का केंद्रीकृत पंजीकरण एवं सत्यापन किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में भूमि अभिलेखों का पूर्ण डिजिटल एकीकरण, स्थान आधारित रिकॉर्ड और बहु-स्तरीय डेटा जांच शामिल हैं। प्रत्येक किसान को 11 अंकीय विशिष्ट डिजिटल पहचान संख्या प्रदान की जा रही है, जिससे एक प्रमाणिक और सटीक किसान डेटाबेस (यूनिफाइड डिजिटल प्रोफाइल) तैयार हो रही है। फार्मर रजिस्ट्री के निर्धारित मानकों का 100 प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। एससीए योजना में भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 713 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। यह डिजिटल व्यवस्था डुप्लीकेशन और फर्जी लाभार्थियों पर प्रभावी रोक लगाएगी और भविष्य की सभी डिजिटल कृषि योजनाओं की मजबूत नींव बनेगी। साथ ही, जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से किसानों को आसान कृषि ऋण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है।

अस्पताल के गेट पर नर्स को गोलियों से भूना

जबलपुर की रहने वाली 26 साल की नर्स की दर्दनाक मौत

सागर (नप्र)। मध्य प्रदेश के सागर जिले में सरकारी अस्पताल में ड्यूटी पर तैनान एक नर्स की गोली मारकर नृशंस हत्या कर दी गई। शाहगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अस्पताल के गेट पर ही नर्स को तीन गोलियां मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी भाग निकला। गोलियों की आवाज से इलाके में दहशत फैल गई।

पुलिस से मिली जानकारी अनुसार सागर जिले के शाहगढ़ में बुधवार रात उस वक्त सनसनी फैल गई, जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ एक युवा नर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावर ने वारदात को अस्पताल के मुख्य द्वार पर ही अंजाम दिया और अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल की ओर फरार हो गया। मृतक नर्स की पहचान 26 वर्षीय दीपशिखा चढ़ार के रूप में हुई है, जो मूल रूप से जबलपुर जिले के पाटन की रहने वाली थी। चश्मदीदों के मुताबिक, दीपशिखा रात के समय स्वास्थ्य केंद्र पर अपनी ड्यूटी पर तैनात थी। जब वह अस्पताल के गेट के पास खड़ी थी, तभी एक अज्ञात हमलावर ने उन पर फायरिंग कर दी।

3 राउंड फायर, दो बाजू व एक पेट में लगी

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हमलावर ने नर्स पर तीन गोलियां चलाईं। दो गोलियां उनके बाजू में और एक गोली सीधे पेट में लगी, जिससे दीपशिखा की मौके पर ही मौत हो गई। गोलियों की आवाज सुनकर जब तक अस्पताल स्टाफ और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, आरोपी मौके से भाग चुका था।

आरोपी अंधेरे का लाभ उठाकर जंगल में भाग गए

घटना की सूचना मिलते ही शाहगढ़ थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। थाना प्रभारी संदीप खरे ने बताया कि आरोपी अंधेरे का लाभ लेकर पास के जंगल की ओर भाग गया है। आरोपी को पकड़ने के लिए पूरे नगर और सीमावर्ती इलाकों में नाकाबंदी कर दी गई है।

पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही

अस्पताल परिसर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है, ताकि आरोपी की पहचान हो सके। पुलिस प्रेम प्रसंग, पुरानी रंजिश और अन्य सभी संभावित एंगल्स पर बारीकी से जांच कर रही है।

जल्द खुलासा होगा, आरोपियों की तलाश कर रहे

नर्स हत्याकांड में शाहगढ़ थाना प्रभारी संदीप खरे के अनुसार पुलिस हर पहलू से मामले की तफ्तीश कर रही है। शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जल्द ही इस अंधे कत्ल का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

डीएफओ जबलपुर ने इस्तीफा दिया, निजी वजह बताई

रीवा, अनूपपुर, दमोह, सतना में रह चुके हैं पदस्थ, पीसीसीएफ को भेजा त्यागपत्र

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश कैडर के 2013 बैच के आईएफएस अधिकारी विपिन पटेल ने इस्तीफा दे दिया है। पटेल वर्तमान में जबलपुर में

डीएफओ योजना के पद पर कार्यरत हैं। इसके पहले वे रीवा, दमोह, सतना और अनूपपुर के डीएफओ रह चुके हैं। पटेल ने इस्तीफा देने की वजह निजी कारण बताया है।

पीसीसीएफ और हॉफ को भेजे इस्तीफे में विपिन पटेल ने कहा है कि वे अपनी आईएफएस सर्विस से अनकंडीशनल इस्तीफा दे रहे हैं, जिसकी वजह निजी है। 4 फरवरी 2026 को भेजे इस्तीफे में पटेल ने कहा है कि उनका इस्तीफा कांपीटेंट अथॉरिटी को फॉरवर्ड करें और आईएफएस सेवा से उन्हें मुक्त किया जाए। पटेल ने इस्तीफे की कॉपी वन विभाग के सचिव को भी भेजी है।

सागर में लोकायुक्त में शिकायत सतना, अनूपपुर में विवादित रहे

आईएफएस अधिकारी विपिन पटेल सतना, अनूपपुर में विवादित रहे थे। उनके विरुद्ध सागर लोकायुक्त पुलिस में भी शिकायत की गई थी। पटेल ने अनूपपुर डीएफओ रहने के दौरान एक विवादित आदेश जारी किया था। जिसका प्रदेश भर में विरोध हुआ था। उनके द्वारा जारी आदेश में कहा गया था उनके क्षेत्राधिकार में वनकर्मियों को उच्च पदभार दिए गए हैं, उसे तत्काल निरस्त कर दिया गया है। आदेश में यह भी लिखा था कि सभी स्टाफ कर्मी मूल पद पर वापस आकर काम करेंगे। डीएफओ विपिन पटेल द्वारा 4 नवंबर को आदेश दिया गया था। इसके बाद मप्र कर्मचारी मंच ने सीएम को पत्र लिखकर इसका विरोध जताया था। दरअसल 15 अक्टूबर को वन विभाग ने आदेश जारी किया था कि 2025 के पदोन्नति आदेश लागू होने की वजह से कर्मचारी मूल पद पर लौटेंगे। इसलिए अब नए कर्मचारियों को उच्च पदभार दिया गया तो इससे प्रमोशन के मामलों में जटिलताएं आएंगी। इसलिए शासन उच्च पदभार वाले पूर्व के निर्देश रद्द करता है। इस पर कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने कहा था कि किसी वन मंडल ने ऐसा आदेश नहीं दिया है। अनूपपुर डीएफओ भी इसके लिए अधिकृत नहीं हैं। ऐसे आदेश का अधिकार सिर्फ सीसीएफ शहडोल को ही है। उन्होंने आरोप लगाया कि डीएफओ सागर और सतना में रहते हुए भी विवादों में रहे थे। सागर में शिकायत के बाद लोकायुक्त में जांच लंबित है।

बीएससी के छात्र को डंपर ने कुचला

परिवार का इकलौता बेटा था, आरोपी चालक मौके से फरार

भोपाल (नप्र)। भोपाल के छोला मंदिर इलाके में बीएससी के एक छात्र को गिट्टी से भरे डंपर ने टक्कर मार दी। हादसे में छात्र की मौत हो गई। चालक डंपर को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। राहगीरों की मदद से छात्र को हमीदिया अस्पताल पहुंचा गया। जहां मौत की पुष्टि होने के बाद शव को मर्चुरी में रखवा दिया गया है। घटना बुधवार-गुरुवार की दरमियानी रात की है। मृतक की शिनाख्त गुरुवार सुबह परिजनों ने की। दोपहर में पीएम के बाद बॉडी परिजनों को सौंप दी गई है। पुलिस ने डंपर को कब्जे में लेकर थाने में खड़ा कर लिया है। मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई है।

भोपाल मेमोरियल परिसर में रहता है परिवार- 21 वर्षीय सूजल मुंडा पुत्र तोनाराम मुंडा निवासी भोपाल मेमोरियल अस्पताल परिसर में रहता था। उसके पिता बीएमएचआरसी के कर्मचारी हैं। वह प्राइवेट कॉलेज से बीएससी फॉरेंसिक से फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रहा था। बुधवार देर रात अयोध्या नगर से दोस्त के घर से खाना खाकर लौट रहा था।

सुनो बिट्टू...मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन भगवान नहीं करेंगे

गुना में बॉयफ्रेंड ने शादी से इनकार किया, लड़की ने फांसी लगाकर दी जान

गुना (नप्र)। गुना की राधा कॉलोनी में रहने वाली एक युवती ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। युवती ने मौत से पहले अपने बॉयफ्रेंड को लिखा- सुनो बिट्टू, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान ने भी माफ कर दिया। खुश रहना मेरी जान। आई लव यू।

जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान राधा कॉलोनी में रहने वाली रिया रघुवंशी (23) के रूप में हुई है। गुना में किराए के कमरे में रहती थी। फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रही थी। इसके साथ ही प्राइवेट कोचिंग में बच्चों को पढ़ाती थी।सुसाइड के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। परिजनों से पूछताछ कर रही।

रिया रघुवंशी, मृतक

युवक के परिजन शादी के लिए तैयार नहीं थे- बताया जा रहा है कि आकाश रघुवंशी और रिया रघुवंशी का पिछले 7 साल से अफेयर चल रहा था। आकाश आकाश रघुवंशी (बिट्टू) बैंक में काम करता है। आकाश रघुवंशी के परिजन रिया से शादी के लिए तैयार नहीं थे। मनाने के बाद भी परिजन नहीं माने तो 15 दिन पहले युवक युवती ने मंदिर में शादी कर ली थी।

शादी की जानकारी आकाश के परिजनों को लगी तो युवती को अपनाने से इनकार कर दिया। परिजनों के मना करने के बाद आकाश ने भी शादी से इनकार कर दिया। बॉयफ्रेंड के इनकार से रिया टेंशन में आ गई थी। बुधवार शाम अपने घर के कमरे में फंदा बनाकर सुसाइड कर लिया।

दरवाजा नहीं खुला तो शक गहराया- पड़ोस में रहने वाली युवतियों के मुताबिक बुधवार शाम को रिया काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं निकली, तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा नहीं खुला, तो युवतियों ने खिड़की से अंदर झांककर देखा। इस दौरान रिया कमरे के अंदर फंदे पर लटकी दिखी। युवतियों ने फौरन पुलिस और परिवार को सूचना दी। जानकारी मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। शव को नीचे उतारा और जिला अस्पताल भेजा। गुरुवार सुबह जिला अस्पताल में शव का पोस्टमॉर्टम किया गया। शव परिवार को सौंप दिया गया है।

रिया के पिता बोले- आकाश ने बेटी को धोखा दिया- रिया रघुवंशी के पिता बृजेश रघुवंशी ने बताया कि बेटी ने उन्हें बताया था कि आकाश शादी नहीं करना चाह रहा है। आकाश के मां-बाप भी मना कर रहे हैं। बेटी बहुत पीड़ा झेल रही थी। आकाश ने बेटी को धोखा दिया। इसी वजह से बेटी ने फांसी लगाई है।

छोला इलाके में छात्राओं पर कटर से हमला, साइको-मैन गिरफ्तार

पत्नी से विवाद के बाद बनाया निशाना, पुलिस ने रखा था 20 हजार का इनाम

भोपाल (नप्र)। भोपाल में तीन छात्राओं पर कटर से हमला करने वाले साइको मैन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसे बुधवार रात छोला इलाके में घेराबंदी कर पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी का नाम देवेंद्र अहिरवार है। वह सागर जिले का रहने वाला है। शुरुआती जांच में पता चला है कि पत्नी से झगड़ा होने के बाद उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए एक बाद एक तीन छात्राओं को निशाना बनाया।

5 टीमें तलाश में जुटी थीं- पुलिस के मुताबिक, आरोपी पर 20 हजार रुपए इनाम था। क्राइम ब्रांच, अयोध्या नगर और पिपलानी थाने की 5 टीमें उसकी तलाश में लगी थी। इसमें करीब 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल थे। इसके लिए पुलिस ने शहर के आपराधिक प्रवृत्ति वालों का डेटा निकालकर भी मैच करने की कोशिश की थी।

100 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज चेक किए- पुलिस के मुताबिक,आरोपी शराब पीने का आदी है और भोपाल में मजदूरी करता है। पुलिस ने बदमाश की तलाश के लिए 100 से

ज्यादा सीसीटीवी कैमरों के फुटेज चेक किए। इसके बाद उसे बदमाश का सुराग लगा।

एक के बाद एक तीन छात्राओं को बनाया निशाना- सिरफिरे देवेंद्र अहिरवार ने 29 जनवरी की रात पत्नी से विवाद किया था। इसके बाद बाइक पर सवार होकर निकला। भानपुर ब्रिज के रास्ते आरोपी अयोध्या नगर और पिपलानी इलाके में पहुंचा। यहां उसने तीन छात्राओं पर कटर से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। दो छात्राओं को गंभीर चोटें आई थीं, जबकि एक को मामूली चोट लगी। 30 जनवरी को पीड़िताओं की शिकायत पर अयोध्या और पिपलानी पुलिस ने दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की थी। आरोपी अलग-अलग स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों में कैद हुआ था।

चेहरे पर रूमाल बांधे था आरोपी- आरोपी ने अपना चेहरा रूमाल से ढंक रखा था। पिपलानी इलाके में ही आरोपी ने एक अन्य युवती पर भी हमला किया था। हालांकि मामूली रूप से घायल हुई थी।

भोपाल में नेटफ्लिक्स की फिल्म घूसखोर पंडत का विरोध

ब्राह्मण संगठनों ने टाइटल-डायलॉग पर जताई आपत्ति, समाज की छवि खराब करने का आरोप

भोपाल (नप्र)। नेटफ्लिक्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही फिल्म घूसखोर पंडत के ट्रेलर को लेकर भोपाल में विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज मध्यप्रदेश ने फिल्म के शीर्षक और संवादों को लेकर आपत्ति जताते हुए डीबी मॉल के सामने प्रदर्शन किया। नेटफ्लिक्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही इस फिल्म के ट्रेलर में बोले गए डायलॉग 'ब्राह्मण लंगोट का ढीला होता है' को विवादित बताया। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने इस संवाद को समाज के लिए अपमानजनक बताते हुए कड़ा विरोध जताया है। संगठन का कहना है कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ब्राह्मण समाज को नीचा दिखाने और उसकी छवि खराब करने का प्रयास है।

संगठन की ओर से एमपी नगर थाने को सौंपे गए पत्र में कहा गया है कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही फिल्म के ट्रेलर में ब्राह्मण समाज के लिए आपत्तिजनक और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। संगठन ने इसे सुनियोजित तरीके से समाज की छवि धूमिल करने का प्रयास बताया है।

प्रदर्शन के दौरान संगठन के कार्यकर्ताओं ने फिल्म से जुड़े कलाकार और निर्माता के खिलाफ

नारेबाजी की। इस दौरान 'मनोज वाजपेयी मुर्दाबाद' के नारे भी लगाए गए। संगठन ने आरोप लगाया कि लगातार फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के माध्यम से ब्राह्मण समाज को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है।

ब्राम्हाण समाज को नीचा दिखाने का प्रयास- अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज मध्यप्रदेश ने मीडिया से बातचीत में कहा कि फिल्म का नाम और संवाद ब्राह्मण समाज को नीचा दिखाने वाले हैं। उनका कहना है कि समाज को लेकर इस तरह के शब्दों का प्रयोग अस्वीकार्य है और इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।